सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 138, नई दिल्ली । सोमवार, 29 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यह मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कर कौन पाएगा।

03 दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर,बेसमेंट में 3 की मौत

06 आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां से कहां पहुंचे ?

08 ओलंपिक में खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका मिला: मोदी

कांवड़ यात्रा: एनसीआर की रफ्तार पर डायवर्जन का ब्रेक

गाजियाबाद में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

कांवड़ यात्रा के कारण शुक्रवार आधी रात से हल्के वाहनों का डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया। इससे कई मार्गों पर वाहन चालकों को परेशानी हुई तो कई स्थानों पर वाहनों को घूमकर लंबी दूरी तय करनी पड़ी। वाहन चालकों की सहूलियत के लिए विभिन्न स्थानों पर होडिंग लगाए गए हैं लेकिन दूसरे शहरों से आने वाले वाहन चालक कई बार रास्तों से अनजान रहने पर भटक जाते हैं।

संजय बाटला

दिल्ली एनसीआर। सावन माह में प्रतिवर्ष भोले के भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर के लिए जाते हैं। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एनसीआर के जिलों में प्रशासन रूट डायवर्जन के साथ ही तमाम मार्गों पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर देता है। इससे न सिर्फ रोजाना आने-जाने वाले नौकरी पेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उद्योग धंधे, बच्चों की पढ़ाई और व्यवसाय पर भी असर पड़ता है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (ईपीई) के निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ (एनएच-नौ) के चौड़ीकरण के बाद यह उम्मीद जगी थी कि साल-दर साल होने वाली इस परेशानी से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन अफसर ऐसा कोई विकल्प तलाश नहीं सके, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुए बिना भोले के भक्तों की यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके।

फिलहाल जिम्मेदारी अधिकारी गाजियाबाद के मुरादनगर से मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के बीच बनाए जा रहे कांवड़ मार्ग से ही इस समस्या के समाधान का दावा कर रहे हैं। कांवड यात्रा के दौरान 15 दिन के लिए होने वाले रूट डायवर्जन से एनसीआर के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पेश है, अवनीश मिश्र की रिपोर्ट-

भारी वाहनों का डीएमई सहित 12 मार्गों पर डायवर्जन

गाजियाबाद: 22 जुलाई की रात 12 बजे से ही भारी वाहनों का डीएमई सहित 12 मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है, जो पांच अगस्त की रात आठ बजे तक रहेगा। 27 जुलाई की रात 12 बजे से हल्के वाहन जैसे चार पहिया निजी व व्यावसायिक वाहन व तीन पहिया वाहनों का भी जीटी रोड सहित 12 रूटों पर डायवर्जन कर दिया गया। डीएमई पर रविवार आधी रात से हल्के वाहन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएंगे।

नोएडा

22 जुलाई से चार अगस्त तक सेक्टर-14ए चिल्ला बॉर्डर से होते हुए ओखला बर्ड सेंचुरी मार्ग तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

शुक्रवार से दिल्ली कालिंदी कुंज से ओखला बर्ड सेंचुरी तक एक लेन बंद कर दी गई है। कालिंदी कुंज, डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर, छिजारसी, मॉडल टाउन के पास यातायात कर्मी तैनात हैं।

कांवड़ का जत्था गुजरने के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात को रोककर कांवड़ियों को सड़क पार कराते हैं।

हापुड़

22 जुलाई से तीन अगस्त की रात 10 बजे तक आठ रूटों पर भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया है।

25 अगस्त से हल्के वाहनों का भी रूट डायवर्जन हो गया है।

मेरठ

दिल्ली-देहरादून हाईवे, गढ़ रोड, हापुड़ रोड, दिल्ली रोड, रुड़की रोड पर रूट डायवर्ट किया जाता है।

पिछले साल की तरह इस बार भी डीएमई को वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने की तैयारी है।

मेरठ के एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने कहा है कि कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर डीएमई को बंद करने के बारे में विचार करेंगे।

400 बसों का बदला गया रूट

गाजियाबाद व कौशांबी डिपो की ये बसें अलग-अलग मार्गों से गंतव्य के लिए जाएंगी। 30 से 70 रुपये तक किराया गाजियाबाद व कौशांबी डिपो की बसों में डायवर्जन की वजह से बढ़ गया है, जिसका असर यात्री पर पड़ेगा 40 रुपये तक किराये में वृद्धि नोएडा डिपो की बसों में रूट डायवर्ट होने की वजह से हो गई है 408 बसों का रूट मेरठ डिपो ने बदला है।

भैंसाली बस डिपो को बंद कर दिया गया है। दिल्ली और हरिद्वार की बसों का संचालन सोहराब गेट डिपो से किया जा रहा है। 154 से 162 रुपये तक अधिक किराया मेरठ से दिल्ली जाने वाली बसों में यात्रियों को देना पड़ रहा है 47 रुपये अधिक किराया मेरठ से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को डायवर्जन के चलते चुकाना पड़ रहा

दिल्ली में रूट डायवर्जन नहीं, बनाते हैं अलग लेन

पूर्वी दिल्ली से ज्यादातर कांवड़िये गुजरते हैं। यहां रूट डायवर्जन के बजाय सड़क पर बैरियर व रस्सी बांधकर कांवड़ियों की अलग लेन बना दी जाती है। वह उसी लेन से गुजरते हैं। इससे सड़क पर यातायात भी चलता रहता है। हालांकि सड़क की चौड़ाई कम हो जाने से जाम की स्थिति बनती है।

आम जन को परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी

400 बसों का रूट बदल दिया गया है, गाजियाबाद व कौशांबी डिपो की ये बसें अलग-अलग मार्गों से गंतव्य के लिए जाएंगी।

30 से 70 रुपये तक किराया गाजियाबाद व कौशांबी डिपो की बसों में डायवर्जन की वजह से बढ़ गया है, जिसका असर यात्री पर पड़ेगा।

40 रुपये तक किराये में वृद्धि नोएडा डिपो की बसों में रूट डायवर्ट होने की वजह से हो गई है।

408 बसों का रूट मेरठ डिपो ने बदला है, भैंसाली बस डिपो को बंद कर दिया गया है। दिल्ली और हरिद्वार की बसों का संचालन सोहराब गेट डिपो से किया जा रहा है।

154 से 162 रुपये तक अधिक किराया मेरठ से दिल्ली जाने वाली बसों में यात्रियों को देना पड़ रहा है 47 रुपये अधिक किराया मेरठ से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को डायवर्जन के चलते चुकाना पड़ रहा

गाजियाबाद में स्कूल बंद

गाजियाबाद में 29 जुलाई से दो अगस्त तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। गौतमबुद्ध नगर में दो अगस्त को स्थानीय अवकाश घोषित होने की वजह से स्कूल-कॉलेज बंद रहेगे। हापुड़ में बृहस्पतिवार से दो अगस्त तक स्कूल-कॉलेज बंद हैं।

कांवड़ मार्ग बनने के बाद दूर हो सकती है समस्या

गाजियाबाद के मुरादनगर से मुजफ्फरनगर के पुरकाजी तक कांवड़ मार्ग का निर्माण चल रहा है। मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों को लेकर मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में जाने से काम में देरी हो रही है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करीब सालभर में मार्ग बन जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो अगले साल रूट डायवर्जन करने की स्थिति नहीं बनने की संभावना है, क्योंकि कांवड़िये इसी मार्ग पर चलेंगे। अन्य मार्ग खाली रहेंगे।

उद्योग-धंधे भी चुका रहे डायवर्जन की कीमत

गाजियाबाद के उद्यमियों के मुताबिक जिले में कांवड़ यात्रा के लिए पहली बार वर्ष 1995 में रास्ते दो दिन के लिए बंद किए गए थे। उद्यमियों ने जिला प्रभारी मंत्री असीम अरुण, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन के साथ उद्योगों को भी राहत देने से संबंधित सुझाव रखे थे।

उन्होंने उत्पाद व कच्चे माल से संबंधित वाहनों को देर रात औद्योगिक क्षेत्र में आवाजाही की अनुमति देने और कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किए जाने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे कच्चे माल मंगाने और तैयार माल को बाहर भेजने में उद्यमियों को परेशानी होती है।

इसके साथ ही कर्मचारियों को भी दफ्तर पहुंचने में परेशानी होती है। इसमें गाजियाबाद और मेरठ जिले के उद्यमियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। गौतमबुद्ध नगर के उद्योगों का रूट डायवर्जन का खास असर नहीं होता है।

200 करोड़ रुपये का कारोबार

गाजियाबाद जिले में 15 दिन में 200 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का दावा उद्यमी कर रहे हैं। वहीं 25 करोड़ रुपये का कारोबार मेरठ में इन 15 दिन में प्रभावित होने का दावा आइआइए के पदाधिकारियों ने किया है।

छत्तरपुर मंदिर के पास आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन की मीटिंग हुई। सभी साथियों ने अवैध बाइकों के खिलाफ एक साथ मिलकर हुंकार भरी, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बाइकों पर रोक लगा रखी है फिर भी दिल्ली मे सेवा दे रही है इसके खिलाफ कार्यवाही करने की सरकार व ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कार्यवाही करें यह दिल्ली के समस्त ऑटो चालकों की मांग है।

उपेन्द्र सिंह (महासचिव)

डॉ. लॉजिस्टिक्स: भारत को विश्व गुरु बनाने में लॉजिस्टिक्स की भूमिका

परिवहन विशेष न्यूज

लॉजिस्टिक्स उद्योग के महत्त्व को समझने और इसे आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से डॉ. अंकुर शरण और परिवहन विशेष ने एक अनूठी पहल की है, जिसका नाम है 'डॉ. लॉजिस्टिक्स'। यह श्रृंखला हिंदी में होगी, जिसमें लॉजिस्टिक्स उद्योग के विभिन्न पहलुओं, इसकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

लॉजिस्टिक्स: एक परिचय

लॉजिस्टिक्स सिर्फ वस्तुओं की ढुलाई और भंडारण तक सीमित नहीं है; यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो उत्पाद की सृजन से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने तक के हर चरण को शामिल करती है। एक कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली न केवल उद्योगों को समय पर और सुरक्षित तरीके से उत्पाद वितरित करने में मदद करती है, बल्कि यह पूरे देश की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करती है।

डॉ. लॉजिस्टिक्स की विशेषताएं

महत्वपूर्ण केस स्टडीज:

इस श्रृंखला में विभिन्न महत्वपूर्ण केस स्टडीज को शामिल किया जाएगा, जो लॉजिस्टिक्स उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले उदाहरणों को प्रदर्शित करेंगी। ये केस स्टडीज न केवल नवाचारों और चुनौतियों को उजागर करेंगी, बल्कि समाधानात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करेंगी।

विशेष साक्षात्कार:

भारत और विश्व के प्रमुख लॉजिस्टिशियन के विशेष साक्षात्कार इस श्रृंखला का प्रमुख आकर्षण होंगे। ये साक्षात्कार दर्शकों को उन चुनौतियों और अवसरों के बारे में

बताएंगे जिनका सामना लॉजिस्टिक्स उद्योग कर रहा है, और कैसे विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं।

लॉजिस्टिक्स का भविष्य:

श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लॉजिस्टिक्स के भविष्य पर होगा, जिसमें उभरती हुई तकनीकों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और ऑटोमेशन के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। यह भाग दर्शकों को भविष्य के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य के लिए तैयार करेगा और उन्हें उद्योग में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूक करेगा।

भारत के विकास में लॉजिस्टिक्स की भूमिका

लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने में है। यह उद्योग न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि भारत को वाणिज्यिक केंद्र बनने की ओर भी अग्रसर करता है। लॉजिस्टिक्स की कुशलता से उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद सुलभ होते हैं।

'डॉ. लॉजिस्टिक्स' श्रृंखला का उद्देश्य न केवल लॉजिस्टिक्स उद्योग के महत्व को समझाना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि कैसे यह उद्योग भारत को विश्व गुरु बनने की ओर ले जा सकता है।

इस श्रृंखला के माध्यम से, हम यह आशा करते हैं कि लोग लॉजिस्टिक्स के बारे में अधिक जानेंगे और इसे अपने जीवन में और अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। आइए, इस पहल का हिस्सा बनें और भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में योगदान दें।

डॉ. अंकुर शरण: एक अद्वितीय लॉजिस्टिक विशेषज्ञ

डॉ. अंकुर शरण लॉजिस्टिक्स उद्योग में 16 से अधिक वर्षों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ऑटोमोटिव कंपनियों और मीडिया उद्योग के लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया है। उनके व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता ने उन्हें एक कुशल और दूरदर्शी लॉजिस्टिक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में, वह विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक गतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं।

डॉ. शरण के पिता, स्वर्गीय श्री अजय शंकर श्रीवास्तव, भारतीय रेल और कॉनकोर (CONCOR) के एक प्रसिद्ध लॉजिस्टिशियन थे। उन्होंने भारत, विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में, विभिन्न लॉजिस्टिक्स हब, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके अनुभव और ज्ञान ने भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉ. अंकुर शरण की यात्रा और उनके पिता की विरासत यह दर्शाती है कि कैसे लॉजिस्टिक्स उद्योग में अनुभव और विशेषज्ञता न केवल व्यक्तिगत करियर में बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ. शरण की विशेषज्ञता और उनके पिता के योगदान से प्रेरित होकर, लॉजिस्टिक्स उद्योग में नए मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं, जो भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायता करेंगे।

पर्यावरण पाठशाला: न्यूनतावादी (Minimalist) दृष्टिकोण अपनाने के लिए दैनिक जीवन में छोटे बदलाव

हमारे चारों ओर प्लास्टिक का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है, चाहे वह हमारे घरों में हो, बाजारों में, या फिर समुद्र में। प्लास्टिक कचरा न केवल हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करना आवश्यक है ताकि हम प्लास्टिक कचरे को कम कर सकें और न्यूनतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकें।

1. पुनः प्रयोज्य बैग और बोतलें:

जब भी हम बाजार या खरीदारी के लिए जाते हैं, तो अपने साथ पुनः प्रयोज्य कपड़े या जूट के बैग ले जाएं। इससे प्लास्टिक बैग्स का उपयोग कम होगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकेगा। साथ ही, पुनः प्रयोज्य पानी की बोतल का उपयोग करें, जिससे प्लास्टिक की बोतलों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

2. एकल उपयोग वाली वस्तुओं से बचें:

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे कि स्ट्रॉ, प्लेट्स, कप्स, और चम्मच को नकारें। इसके बजाय, धातु, बांस, या कांच से बनी वस्तुओं का उपयोग करें जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और बार-बार इस्तेमाल की जा सकती हैं।

3. प्लास्टिक पैकेजिंग कम करें:

खरीदारी करते समय प्लास्टिक में पैक की गई वस्तुओं से बचें। इसके बजाय, खुले में उपलब्ध वस्त्रों, सब्जियों, और फलों को खरीदें। आप अपने साथ पुनः प्रयोज्य कंटेनर भी ले जा सकते हैं।

4. कचरा पृथक्करण:

घरों में कचरे का सही तरीके से पृथक्करण करें। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करें और उन्हें पुनर्चक्रण योग्य वस्त्रों में बदलने के लिए तैयार रखें। इससे कचरे को सही तरीके से निपटाने में मदद मिलेगी।

5. न्यूनतम उपभोग:

न्यूनतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने उपभोग की आदतों पर ध्यान दें। आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीदने और उपयोग करने से बचें। इसके बजाय, केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदें जो वास्तव में आवश्यक हों।

6. घरेलू उत्पादों का चयन:

घर में उपयोग होने वाले उत्पादों में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करें। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल क्लीनिंग उत्पाद, बांस के टूथब्रश, और प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद। इससे प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

7. जागरूकता और शिक्षा:

परिवार और मित्रों के बीच प्लास्टिक कचरे के प्रभाव और पर्यावरण के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्लास्टिक कचरे को कम करने और न्यूनतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए ये छोटे-छोटे कदम हमारे जीवन को न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाएंगे, बल्कि हमें अधिक स्वस्थ और सशक्त भी बनाएंगे। पर्यावरण पाठशाला के माध्यम से, हम सभी को इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरित पृथ्वी सुनिश्चित की जा सके।

indiangreenbuddy@gmail.com
X @GreenBuddy2024

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बढ़ रहा है वजन, महिलाएं फॉलो करें ये टिप्स, तेजी से होगा वेट गेन

दुबली-पतली महिलाएं आमतौर पर वेट गेन करने के लिए अनगिनत नुस्खे आजमाती हैं, मगर हेल्दी डाइट फॉलो करने के बावजूद भी कई बार वजन नहीं बढ़ पाता है. ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन महिलाओं के लिए बेस्ट हो सकता है.

स्लिम एंड ट्रिम लुक कैरी करने के लिए महिलाएं कई तरीके अपनाती हैं. इसके बावजूद कुछ महिलाएं मोटापे का शिकार होने लगती हैं. तो वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, जो अपने दुबलेपन को लेकर परेशान रहती हैं. अगर आपका वजन काफी कम है तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इन चीजों को डाइट में शामिल करके आप आसानी से वेट गेन (Weight gain tips) कर सकती हैं.

पतली और दुबली महिलाएं अक्सर अपने फिगर को लेकर टेंशन में रहती हैं. वहीं पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने के बाद भी कई बार महिलाओं का वजन बढ़ने का नाम नहीं लेता है. ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन आपको वेट गेन करने में मदद कर सकता है. तो आइए ओन्लीमाईहेल्थ डॉट कॉम के अनुसार, जानते हैं वजन बढ़ाने के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके महिलाएं खुद को फिट और हेल्दी रख सकती हैं.

प्रोटीन का सेवन करें

नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन को बॉडी का बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है. खासकर प्लांट बेस्ड प्रोटीन में शुगर और फैट भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है, जिससे मसल्स बिल्डिंग में काफी मदद मिलती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है. ऐसे में आप पनीर, फुल क्रीम मिल्क, दही और दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में शामिल कर सकती हैं. साथ ही चिकन, अंडा, लाल मीट, मिल्क पाउडर और प्रोटीन पाउडर जैसी चीजों से आप आसानी से वेट गेन कर सकती हैं.

फैट रिच डाइट लें

वजन बढ़ाने के लिए महिलाएं फैट से भरपूर चीजों को भी डाइट में एड कर सकती हैं. ऐसे में घी, मक्खन, नट्स और गुड फैट से भरपूर चीजों का सेवन करना महिलाओं के लिए बेस्ट होता है. इससे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है और महिलाओं के वजन में भी इजाफा देखने को मिलने लगता है.

कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खाएं

कार्बेहाइड्रेट से भरपूर चीजें बॉडी में कैलोरी इन टेक को बढ़ावा देती हैं. जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसे में वेट गेन करने के लिए महिलाएं आलू, शकरकंद, ओट्स, ग्रेन और ब्राउन राइस का सेवन कर सकती हैं. वहीं घी और बटर से युक्त चीजें खाने से भी वेट गेन फास्ट होने लगता है.

वजन ना बढ़ने के कारण

महिलाओं में वजन ना बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. दरअसल कई बार महिलाओं के शरीर में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते हेल्दी डाइट लेने के बावजूद महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है और उनका वजन कम रहता है. इसके अलावा इंफ्लेमेटरी डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज और हाइपोथायरॉयडिजम के चलते भी महिलाओं का वजन नहीं बढ़ता है।

भारत की 5 महिला खिलाड़ी, जीवन के संघर्षों से कभी नहीं मानी हार, आज दुनिया मानती है लोहा

महिलाओं का दबदबा खेल जगत में भी बढ़ा है. भारतीय खेल के इतिहास में कई ऐसी महिलाएं युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हैं, जिन्होंने तमाम परिस्थितियों के बावजूद देश का परचम दुनियाभर में फैलाया है. आज कई भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. उनकी रैंकिंग भी दुनिया की टॉप खिलाड़ियों में शामिल हो गई है. जिन खेलों में अब तक पुरुषों का दबदबा था, वहां भी महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है. 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' पर जानते हैं देश की नामी महिला खेलाड़ियों के संघर्षपूर्ण अचीवमेंट के बारे में.

विश्व महिला क्रिकेट में झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) की उपलब्धियां कम नहीं हैं. उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 से ज्यादा ओवर लेने वाली दुनिया की इकलौती गेंदबाज हैं. कभी ऐसा था कि गली क्रिकेट में उनकी धीमी गेंदबाजी पर मोहल्ले के लड़के चौके-छक्के लगाया करते थे, लेकिन झूलन ने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए मेहनत किया और आज उनके नाम इतने खिताब हैं. बता दें कि उन्होंने कुल 333 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं. (Image: Jhulan Goswami-Instagram)

2/5 भारतीय मुक्केबाद जमुना बोरो (Jamuna Boro) असम के छोटे से कस्बे ढेकियाजुली के पास बेलसिरी गाँव से ताल्लुख रखती हैं. बचपन में ही बोरो के के पिता का निधन हो गया और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए अकेली मां खेती और चाय व सब्जियां बेचा करती थीं. छोटी जमुना बचपन में ही मुक्केबाद बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने मनोबल गिराने वाली कई बातें कहीं. लेनिक जमुना ने हार नहीं माना और मुक्के बा जी को ही अपना क रि य र बनाया. आज जमुना बोरो 54 किलोग्राम वर्ग में भारत की नम्बर एक मुक्केबाज हैं और विश्व रैंक में जमुना टॉप 5 में शामिल रह चुकी हैं. उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता है.

भारतीय मुक्केबाद जमुना बोरो (Jamuna Boro) असम के छोटे से कस्बे ढेकियाजुली के पास बेलसिरी गाँव से ताल्लुख रखती हैं. बचपन में ही बोरो के के पिता का निधन हो गया और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए अकेली मां खेती और चाय व सब्जियां बेचा करती थीं. छोटी जमुना बचपन में ही मुक्केबाद बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने मनोबल गिराने वाली कई बातें कहीं. लेनिक जमुना ने हार नहीं माना और मुक्केबाजी को ही अपना करियर बनाया. आज जमुना बोरो 54 किलोग्राम वर्ग में भारत की नम्बर एक मुक्केबाज हैं और विश्व रैंक में जमुना टॉप 5 में शामिल रह चुकी हैं. उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता है.

3/5 भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज (Anju Bobby George) विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं. केरल में जन्मी अंजू को बचपन से ही उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीते. साल 2003 में पेरिस में आयोजित हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में जब अंजू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, तो पूरा देश हतप्रभ था. वह भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं. (Image : Anju Bobby George-Instagram)

भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज (Anju Bobby George) विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं. केरल में जन्मी अंजू को बचपन से ही उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीते. साल 2003 में पेरिस में आयोजित हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में जब अंजू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, तो पूरा देश हतप्रभ था. वह भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं.

4/5 असम के नागौड जिले की एथलीट हिमा दास (Hima Das) को आज कौन नहीं जानता. छोटे कद की इस भारतीय धाविका ने दुनियाभर को चौंका दिया था. महज 20 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी पुरुष खिलाड़ी के लिए भी आसान नहीं था. बता दें कि हिमा दास के परिवार में 17 लोग थे जो धान की खेती पर आश्रित थे. वह परिवार की मदद के लिए खेतों में बुआई करती थीं, लेकिन जब उनको उड़ने का मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया है कि गरीबी किसी के हुनर को नहीं छीन सकती. हिमा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते और आईएएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि हासिल की.

असम के नागौड जिले की एथलीट हिमा दास (Hima Das) को आज कौन नहीं जानता. छोटे कद की इस भारतीय धाविका ने दुनियाभर को चौंका दिया था. महज 20 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी पुरुष खिलाड़ी के लिए भी आसान नहीं था. बता दें कि हिमा दास के परिवार में 17 लोग थे जो धान की खेती पर आश्रित थे. वह परिवार की मदद के लिए खेतों में बुआई करती थीं, लेकिन जब उनको उड़ने का मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया है कि गरीबी किसी के हुनर को नहीं छीन सकती. हिमा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते और आईएएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि हासिल की.

5/5 भारतीय महिला खिलाड़ियों में मैरी कॉम (MC Mary Kom) का नाम कई उपलब्धियों से भरा है. खिलाड़ी ही नहीं, वो महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा श्रोत हैं. महान भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम ने महान उपलब्धियों से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है. मैरी कॉम एक अकेली भारतीय महिला बॉक्सर हैं जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है. तीन बच्चों की मां रहते हुए भी उन्होंने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया. Image : Mary Kom Instagram

भारतीय महिला खिलाड़ियों में मैरी कॉम (MC Mary Kom) का नाम कई उपलब्धियों से भरा है. खिलाड़ी ही नहीं, वो महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा श्रोत हैं. महान भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम ने महान उपलब्धियों से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है. मैरी कॉम एक अकेली भारतीय महिला बॉक्सर हैं जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है. तीन बच्चों की मां रहते हुए भी उन्होंने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया.

कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक टेक्नीक से बाल-बाल बची ब्रिटनी विलियम्स की जान, अपनी स्टोरी शेयर कर कही, ना करें 2 संकेतों को इग्नोर

कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर तुरंत दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है.कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर तुरंत दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है.

आज लोगों में कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं. कम उम्र में ही पुरुष हों या महिलाएं, हर कोई हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्या का शिकार हो रहा है. कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों को समय पर ना पहचान पाने के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. हालांकि, ब्राजील की रहने वाली ब्रिटनी विलियम्स नाम की महिला की किस्मत इस मामले में अच्छी साबित हुई थी. मात्र 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटनी को कार्डियक अरेस्ट आया था. वह अचानक बेहोश हो गई थीं और आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. दो दिनों के बाद जब उन्हें होश आया तो पता चला कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था.

टूडे डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, मात्र 24 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण ब्रिटनी विलियम्स की जान जाने ही वाली थी. यह घटना वर्ष 2014 की है. पूरे 9 वर्ष बाद ब्रिटनी ने अपनी कार्डियक अरेस्ट के दौरान हुई स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित जानकारी टुडे शो में एक इंटरव्यू के दौरान साझा की है. ब्रिटनी ने शो में उन लक्षणों के बारे में भी बताया, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज़ कर दिया था. जब ब्रिटनी को कार्डियक अरेस्ट आया था, तो उस दौरान उन्हें कोई भी लक्षण महसूस नहीं हुए. अचानक वो बेहोश हो गईं. इंटरव्यू में वो बताती हैं कि यदि उन्हें तुरंत वहां मौजूद लोगों ने सीपीआर ना दिया होता तो आज वो जिंदा नहीं होती. ब्रिटनी ने शो में सीपीआर ट्रेनिंग लेने के महत्व पर भी जोर दिया.

कार्डियक अरेस्ट के संकेत

कार्डिएक अरेस्ट तब होता है, जब एलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण हृदय की मांसपेशियां खराब हो जाती हैं, जिससे दिल का धड़कना अचानक बंद हो जाता है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (यूएस) के अनुसार, लगभग 90% लोग जिन्हें हॉस्पिटल के बाहर कार्डियक अरेस्ट आता है, उनकी मौत हो जाती है. यदि सही समय पर पीड़ित को सीपीआर दे दिया जाए तो काफी हद तक जान बचाई जा सकती है. इसके लिए सीपीआर देने के बाद तुरंत ही दिल को सामान्य लय में वापस लाने के लिए डिफाइब्रिलेटर का उपयोग भी करना चाहिए. लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक समझने की गलती कर बैठते हैं. हार्ट अटैक तब आता है, जब हार्ट में ब्लॉकेज हो. हालांकि, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बिना किसी वॉर्निंग साइन के आ सकता है. लेकिन, ब्रिटनी ने कुछ लक्षणों को इग्नोर करने की भूल की जो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने से पहले महसूस हुए थे.

ब्रिटनी ने किया इन लक्षणों को नजरअंदाज

ब्रिटनी ने इंटरव्यू में कहा कि जब वह काम पर थीं, तब शरीर के बाईं ओर सुन्नपन, झुनझुनी और सनसनी जैसे लक्षणों को महसूस किया था. इलाज करने के बाद पता

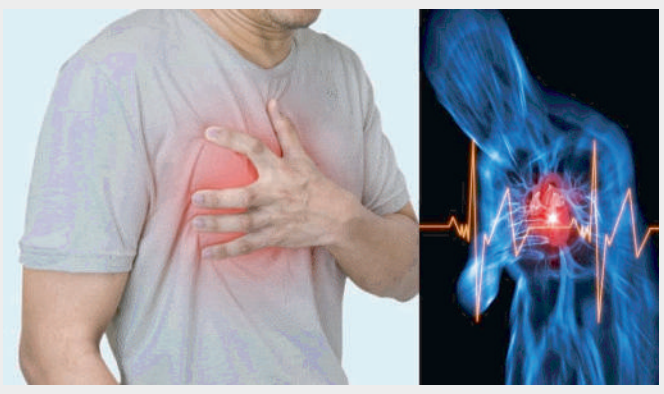

चला कि ब्रिटनी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम (QT syndrome) से ग्रस्त थीं. यह एक ऐसी समस्या है, जिसमें हार्टबीट तेज और अनियमित हो जाता है. अधिकतर लोग लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं. कई बार यह दवाओं के कारण भी हो सकता है. अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार इसे सीजर (seizure) या मिर्गी समझ लिया जाता है. इसका इलाज दवाओं और जीवनशैली में बदलाव लाकर किया जाता है.

कार्डियक अरेस्ट के कॉमन लक्षण

अचानक बेहोश होकर गिर जाना
नाड़ी का रुक जाना
सांस का रुकना
कार्डियक अरेस्ट आने से पहले सीने में तकलीफ
सांस लेने में तकलीफ महसूस करना
कमजोरी महसूस करना
दिल का तेजी से धड़कना
इस तरह के लक्षण यदि आपको कभी भी नजर आएं, तो भूलकर भी इंग्नोर ना करें. ये कार्डियक अरेस्ट आने से पहले के संकेत हो सकते हैं. अक्सर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं जैसा कि ब्रिटनी के मामले में हुआ. ब्रिटनी ने भी कार्डियक अरेस्ट आने से पहले शरीर में सुन्नपन, झुनझुनी या सनसनी जैसे लक्षण महसूस किए थे, लेकिन उसने लोगों की कही हुई बातों के आधार पर इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर दिया था.

कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर का महत्व

जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो बहुत जरूरी है कि उसके पास तुरंत कोई मेडिकल हेल्प पहुंच जाए. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर (CPR) ऐसे में लाभ पहुंचाता है. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हार्ट को कम्प्रेशन देकर एक विद्युत आवेग बनाने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय दोबारा से पंप करने लगता है. ऐसे में आज हर किसी को सीपीआर देने की टेक्नीक को सीखना बेहद जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप पीड़ित की जान बचाने में सफल हो सकें. ब्रिटनी विलियम्स भी अब कुछ ऐसा ही करने में जुटी हुई हैं, ताकि उन्हीं की तरह दूसरे लोगों की भी जान बच सके.

दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर, बेसमेंट में 3 की मौत

परिवहन विशेष न्यूज

एसडीसेठी। राजधानी दिल्ली में सिविक ऐजेंसियों के भ्रष्टाचार से पनप रहे कुकर मुत्ते की तरह जगह-जगह आईएएस, आईपीएस , और डॉक्टर बनाने के चल रहे कोचिंग सैंटर में कभी आग की लपट के बाद अब बेसमेट 12 फीट तक पानी में डूबने से तीन स्टूडेंट्स को मौत की नींद सुला दिया। भ्रष्टचार की भेंट चढे इन स्टूडेंट्स को न्याय दिलवाने की जगह संबंधित महकमें की मंत्री आतिशी समेत एमसीडी मेयर उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों को आर्डर-दर आर्डर देने के साथ जांच कराने की बात कहकर अपना पल्ला झटकने में.लगी है। यह आरोप कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने लगाए हैं। उन्होने रविवार को कहा कि शर्म की बात है दिल्ली सरकार और नगर निगम की लापरवाही ने तीन छात्रो की जान ले ली है। जबकि मुखर्जी.नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद कोर्ट ने एमसीडी,समेत दिल्ली सरकार को तगडी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इन कोचिंग सेंटर्स को चलाने के लिए बाकायदा गाईड लाइंस तैयार की थी। बावजूद इसके कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उडाते हुए भ्रष्टाचार में डूबी सिविक एजेंसियों के अपने नियम कायदे चल रहे हैं।वह कोर्ट को भी ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ रसब चलता है रके नियम को फॉलो कर रहे हैं। वर्ना दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर के बेसमेंट में राव आईएएस कोचिंग सेंटर चल कैसे रहा था। बता दें कि शनिवार को दिल्ली में आई बरसात ने सीवर और नालों के चौंक होने के चलते शाम 7:00 बजे के करीब दो मिनट में सीवर का मल्लयुक्त गंदा पानी बेसमेट में तेजी से घुसा और देखते-देखते 12 फीट तक पानी भर गया। उस वक्त बेसमेट में 30 के करीब स्टूडेंट्स लायब्रेरी में मौजूद थे।शुरू में जैसे तैसे स्टूडेंट्स बाहर निकल आए। मगर जब स्टूडेंट्स की गिनती की गई तो बेसमेंट में और स्टूडेंट्स के फंसे होने से हडकंप मच गया। आनन- फानन में पुलिस, फायरब्रिगेड को इतला दी गई। जब-तक बेसमेंट में 12 फीट पानी भर चुका था। फायरब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने खोजबीन करनी शुरू की तो एक के बाद एक तीन स्टूडेंट्स की डेड बॉडी बाहर निकाली गई। मृतकों की पहचान श्रेया यादव,तानिया सोनी, और नेविन डेल्विन के रूप में की गई। इनमें एक तेलगाना, केरल, और यूपी स्टेट के बताए गए है। उल्लेखनीय है कि कानून के मुताबिक बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था में रिश्वत के बल पर सब कुछ चल रहा है। चाहे कोर्ट का डंडा कितना भी बडा हो।मुखर्जी नगर समेत दूसरी जगह भी नियमों के खिलाफ दडबे नुमा कमरों में कोचिंग सेंटर चल रहे है। बस हादसे का इंतजार होता है और फिर जांच का ड्रामा। फिर सब वहीं डर्रा चलने लगता है। यहां भी जल मंत्री आतिषी ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है। उधर अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी एक्शन मोड में आ गए है।एलजी ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली है। दरअसल आरोप है कि एमसीडी द्वारा दिल्ली के नालों,सीवरों की सफाई नहीं हुई है।इस वजह से राजधानी दिल्ली में बरसात के पानी की उचित निकासी नहीं हो पाती है। और यह पानी, सडकों, गलियों, घरों,समेत बेसमेंट में भर जाता है। बता दें कि शुक्रवार की बरसात ने छतर पुर की विधानसभा के अन्तर्गत गांव असोला,फतेह पुर बेरी की वाल्मिकी बस्ती के घरों में 4-5 फीट पानी भर गया था ।वहां के निवासियों ने एमसीडी के सेंट्रलाइज हेल्प नंबर 155 203 पर सहायता के लिए कई बार फोन लगाया। पर किसी ने फोन तक अटेंड नहीं किया। जबकि बस्ती वालों ने पुलिस और फायरब्रिगेड को भी फोन किया। लेकिन कोई भी सरकारी अमला उनकी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। वाल्मीकी बस्ती के देवेन्द्र प्रधान ने बताया कि इलाकई विधायक, करतार सिंह तंवर, पार्षद सुरेंद्र तंवर समेत सांसद रामबीर सिंह विधुडी तक हाल चाल लेने तक नहीं आए। अब ओल्ड राजेन्द्र नगर में तीन छात्राओं की कोचिंग सेंटर के बेसमेट में ही डूबने से हुई मौत ने सिविक ऐजेंसियों की पोल खोल दी है। रविवार को स्टूडेंट्स करोल बाग मैट्रो स्टेशन के नीचे सडक पर धरने पर बैठ गए है। और न्याय की मांग कर रहे हैं। बहरहल कोचिंग सेंटर हादसे में बीएनएस की धारा-105,106 (1),115/2,290,और 35 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। और कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता, और कोऑर्डिनेटर देश पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

3 स्टूडेंट की डूबने से मौत

श्रेया यादव,
उम्र- 25 साल

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थीं।

जुलाई 2024 में ही राउ कोचिंग सेंटर जॉइन किया था।

नेविन डाल्विन,
उम्र- 28 साल

वे केरल का रहने वाले थे। 8 महीने से IAS की तैयारी कर रहे थे।

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PHD भी कर रहे थे।

तान्या सोनी,
उम्र- 25 साल

तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली थीं।

दिल्ली के अग्रसेन कॉलेज की स्टूडेंट थीं। पिछले साल से कोचिंग ले रही थीं।

कोचिंग सेंटर में कैसे भरा पानी? जिसने ली तीन छात्रों की जान; दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चंद मिनटों में पानी भर गया था। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। वहां कई छात्र मौजूद थे। पानी भरने के दौरान तीन छात्रों को छोड़कर सभी निकलने में कामयाब रहे। इस वजह से उनकी मौत हो गई। बेसमेंट पानी घुसने की वजह कांच का टूटना है। हालांकि दिल्ली पुलिस सही कारण का पता लगा रही है।

नईदिल्ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर में पानी भरने से दो छात्राओं समेत तीन छात्रों की मौत ने झकझोर दिया है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट चल रही लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से आईएएस की तैयारी करने वालों की डूबने से मौत हो गई। उनसे पहले फंसे कई छात्रों को बाहर निकाल लिया था।

इस वजह से बेसमेंट में भरा पानी

बेसमेंट में जाने के लिए कांच के दरवाजे में बायोमैट्रिक सिस्टम लगे होने के कारण छात्रों को अंगूठा लगाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि शाम करीब सात बजे कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर कुछ बड़े वाहनों द्वारा यूटर्न लेने के कारण पानी के प्रेशर से बेसमेंट में जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर लगे कांच का दरवाजा टूट गया, जिससे पानी एकदम से बेसमेंट में जाना शुरू हो गया।

चंद सेकेंड में बेसमेंट में भरा पानी

पानी का बहाव इतना तेज था कि चंद मिनट में बेसमेंट में काफी पानी जमा हो गया। आनन-फानन छात्र बेसमेंट से बाहर निकलने लगे। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाने से बिजली भी चली गई। हादसे में दो छात्रा व एक छात्र अंदर फंसे रह गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

सही कारण का पता लगाया जा रहा

पुलिस ने बताया कि बेसमेंट में पानी घुसने के सही कारण का अभी पता नहीं लग पाया है। पोस्टमॉर्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में छात्रों की डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।

मृतक छात्रों की हुई पहचान

मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम. हर्षवर्धन ने बताया- तीनों पीड़ित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अभ्यर्थी थे, जो राऊ आईएएस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे थे। तीनों पीड़ितों की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर (यूपी) की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के निविन डाल्विन के रूप में की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शवों का आरएमएल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए।

बेसमेट का व्यवसायिक इस्तेमाल आपराधिक गतिविधि, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो- दुर्गेश पाठक

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत की है। ''आप'' के वरिष्ठ नेता एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का कहना है कि बेसमेट का व्यवसायिक इस्तेमाल एक आपराधिक गतिविधि है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी दिल्ली में बहुत सारे लोग बेसमेंट का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नियम विरुद्ध बेसमेंट में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो भविष्य में कोई और घटना हो सकती है। इसलिए कोचिंग सेंटर में हुई घटना की पूरी पारदर्शिता से जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त है। भाजपा ने 15 साल में ड्रेनेज पर कोई काम नहीं किया। ड्रेनेज की सफाई व डी-सिल्टिंग को लेकर मैं डीजेबी के सीईओ और एमसीडी के अफसरों से मिला था और उनसे सीवर के ब्लाक होने और पाइप टूटने की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें राजनीति में नहीं पड़ना है, बल्कि इसका समाधान तलाशना है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि जिस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से यह दुखद घटना हुई है, उस बेसमेंट से पानी को निकाल दिया गया है। लेकिन अब बहुत हो गया। केवल राजेंद्र नगर ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोग बेसमेंट को कमर्शियल गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस कोचिंग संस्थान में घटना हुई है, वहां जल भराव होता है। बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। इस दौरान कोई गाड़ी वहां से गुजरी और उससे टक्कर लगकर बेसमेंट का दरवाजा टूट गया और बेसमेंट में पानी भर गया। सवाल यह है कि बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे। कोचिंग संस्थान ने बेसमेंट में लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह पूरी तरह से आपराधिक गतिविधि है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, इसमें जिन अफसरों की मिलीभगत शामिल हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी।

दुर्गेश पाठक ने कहा कि नाले की डी-सिल्टिंग हुई है। फिर भी इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद 20 दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ और एमसीडी के अधिकारियों से मिला था। उनसे नालों की डी-सिल्टिंग और सफाई की बात की। सुपर शकर व डिक्की मशीनों की मांग कर रहा हूं, लेकिन जहां 10 मशीनें लगनी हैं, वहां दो मशीनें आ रही हैं। दो घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं। उसमें कमी है। अगर नियम विरुद्ध बेसमेंट में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों और कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। आज पानी भरने से घटना हुई, कल कोई और घटना हो सकती है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त है। इसका कारण यह है कि एमसीडी में 15 साल भाजपा की सरकार रही। भाजपा ने ड्रेनेज के उपर कोई काम नहीं किया। पिछले एक साल से हमारी सरकार है और हम लोग ड्रेनेज पर काम कर रहे हैं। मैं किसी दोषारोपण में नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। भाजपा वाले राजनीति करेंगे, हमें उनकी राजनीति में नहीं जाना है। हमें समाधान पर जाना है। इसका समाधान यही है कि जब तक बेसमेंट में चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पूरी दिल्ली के अंदर जमीन पर उतरना होगा और एक-एक घर में जाकर देखना होगा। किसी भी घर के बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधि हो रही है तो उसको सील करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि हम मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर

चर्चा करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 20 दिन पहले मैं डीजेबी के सीईओ और एमसीडी के अफसरों से मिला हूं। कई जगह सीवर ब्लाक है, कई जगह पाइप लाइन टूटी हुई हैं, उनको बदलने की जरूरत है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

कोचिंग सेंटर का मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार

राव कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में स्टोर बनाने की अनुमति नगर निगम व फायर विभाग ने दी थी। डूबकर मरने वाले छात्रों की पहचान हो गई है। बेसमेंट में पानी घुसने के सही कारण का अभी पता नहीं लग पाया है। पोस्टमॉर्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में छात्रों की डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने कई लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगमकर्मियों व अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

बीएनएस की धारा 105, 106 (1), 115 (2), 290, 3 (5) के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं गैर जमानती हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल सजा का प्रावधान है। मामले में पुलिस ने फिलहाल राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक (सीईओ) अभिषेक गुप्ता

व कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

लापरवाह होते जाएंगे गिरफ्तार

अन्य के भूमिका क जांच की जा रही है। जिनकी भी लापरवाही का पता चलेगा, उन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। अभी इस कोचिंग सेंटर को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एफएसएल ने इकट्ठा किए नमूने

रविवार को एफएसएल की टीम ने घंटों कोचिंग सेंटर से नमूने जुटाए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। उधर, बेसमेंट में डूबकर मरने वाले छात्रों के शवों की भी पहचान कर ली गई है। इनमें छात्र का नाम नेविन डाल्विन नेविन है, डाल्विन मूलरूप से एर्नाकुलम (केरल) का रहने वाला था।

ओल्ड राजेंद्र नगर में जगह-जगह चल रहा जानलेवा 'खेल' 4000 लाइब्रेरी में से 95 प्रतिशत बेसमेंट में चल रहीं

परिवहन विशेष न्यूज

ओल्ड राजेंद्र नगर में 4000 से ज्यादा लाइब्रेरी चलती हैं उनमें से 95 प्रतिशत लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही हैं। यहां भी राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की तरह हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में बारिश के समय पानी भर जाता है जिस कारण यहां छात्रों के जाने पर रोक लगा दी जाती है।

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर (Old Rajendra Nagar) में चल रही कोचिंग (Coaching Center) में हुए हादसे ने राजधानी की उन तमाम कोचिंग सेंटर्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके पुस्तकालय या कक्षाएं बेसमेंट में चल रहे हैं। अधिकतर कोचिंग सेंटर का बेसमेंट हाईकोर्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार नहीं हैं और हर साल वर्षा के कारण जलभराव से बेसमेंट में पानी भर जाता है।

फिर भी कोचिंग सेंटर अपने भीड़भाड़ वाले बेसमेंट पुस्तकालय का संचालन जारी रखते हैं। जबकि नियमों के तहत उनको यहां न तो कक्षाओं को चलाने का अनुमति है और न ही पुस्तकालय चलाने की।

बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति

बेसमेंट में केवल भंडारण की ही अनुमति है। बेसमेंट का पुस्तकालय (Library) के रूप में उपयोग करना अपने आप में मानदंडों का उल्लंघन है, क्योंकि एनओसी में उल्लेख किया गया है कि इसका उपयोग केवल भंडारण के लिए किया जाना है।

आने-जाने का हो पर्याप्त रास्ता

अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, यदि किसी भवन के बेसमेंट का उपयोग कार्यालय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो वहां पर्याप्त संख्या में निकास और पहुंच मार्ग होने चाहिए। लेकिन राव आईएएस कोचिंग सेंटर में, केवल एक ही प्रवेश मार्ग था, जिसमें भी प्रवेश बायोमीट्रिक से होता था। लेकिन शनिवार को हुए हादसे के दौरान बिजली जाने से बायोमीट्रिक ने काम करना बंद कर दिया था। यह मानदंडों का एक बड़ा उल्लंघन था।

बैकअप पावर का नहीं था उपाय

नियमों के तहत जब किसी दरवाजे को खोलने के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम होता है, तो बैकअप पावर और एक वैकल्पिक उपाय होना चाहिए, ताकि बिजली कटौती या अन्य किसी समस्या के कारण दरवाजों को तुंरत खोला जा सके। यह स्पष्ट रूप से इस मामले में मौजूद नहीं था।

इन तथ्यों के बावजूद, दिल्ली फायर विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने नौ जुलाई 2024 को तीन वर्ष के लिए राव कोचिंग सेंटर को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया। इसका मतलब है कि उस समय केवल एक दरवाजे वाले बेसमेंट का इस्तेमाल पुस्तकालय के रूप में किया जा रहा था।

हालांकि, प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है कि बेसमेंट का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता है। प्रमाणपत्र में यह भी दावा किया गया है कि कोचिंग सेंटर ने सभी अग्नि सुरक्षा और रोकथाम आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जो स्पष्ट रूप से गलत है। यहां पढ़ने वाले उम्मीदवारों ने बताया कि बेसमेंट का उपयोग बिना अनुमति के पुस्तकालय के रूप में किया जा रहा था। बेसमेंट से कोई खुला अग्नि निकास नहीं था, जो कि एक प्रमुख उल्लंघन हैं, जिसके कारण मौतें हुई।

बेसमेंट में चलती हैं कक्षाएं और पुस्तकालय

ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ व क्लर्क समेत अन्य तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चल रही हैं। इनमें लगभग चार हजार पुस्तकालय व कक्षाएं चल रहे हैं उसमें भी 95 प्रतिशत कक्षाएं व पुस्तकालय बेसमेंट में हैं। यहां के निवासियों ने बताया कि हर साल वर्षा का पानी बेसमेंट में भर जाता है।

इस समस्या को लेकर वो लोग लगातार नगर निगम और एमएलए दुर्गेश पाठक को शिकायत कर रहे हैं। लेकिन हर बार उनकी चिंताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। निवासियों का आरोप है कि कोचिंग सेंटर में हुआ हादसा नगर निगम और दिल्ली सरकार की कमी के चलते हुआ है।

सभी कोचिंगों ने बंद किया बेसमेंट

यहां विभिन्न कोचिंगों में यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने बताया कि बेसमेंट में हुए हादसे के बाद आसपास की अन्य कोचिंगों ने भी बेसमेंट में बने पुस्तकालय में जाने पर रोक लगा दी है। यहां तक की जो कक्षाएं बेसमेंट में चल रही थी वो भी बंद थी। उम्मीदवारों ने बताया कि पुस्तकालय के लिए प्रति व्यक्ति कोचिंग संचालक तीन से चार हजार रुपये वसूलते हैं।

इसमें उन्हें आठ से नौ घंटे तक पढ़ने की अनुमति है। पुस्तकालय आम दिनों में रात को बंद हो जाता है। लेकिन परीक्षा का समय जब नजदीक आता है तो ये 24 घंटे खुला रहता है। बेसमेंट में चल रहे पुस्तकालयों में जगह इतनी छोटी होती है यहां केवल कुर्सी और मेज ही रखी रहती है। इसमें 20-25 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है।

उम्मीदवारों ने बताया कि वो इन पुस्तकालयों में बैठकर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर पढ़ने का वातावरण मिलता है। उम्मीदवारों का आरोप है कोचिंग सेंटर ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र ले रखा है लेकिन वो केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं। अग्नि सुरक्षा नाम मात्र की है। आग बुझाने के लिए उपकरण तो लगे हैं लेकिन कभी माक ड्रिल नहीं हुआ है। किसी को आग बुझाने वाली मशीनों को चलाना तक नहीं सिखाया। आज पानी भरने से इतना बड़ा हादसा हुआ है कल को आगजनी का कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने की शर्तें

सीढ़ियों तक जाने वाले सभी निकास मार्ग को ताले और चाबियों से मुक्त और साफ रखा जाना चाहिए।

वहां प्रदान की गई सभी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं हर समय अच्छी कार्यशील स्थिति में बनी रहेंगी।

गैर-कार्यात्मक सुरक्षा उपायों के कारण जान या संपत्ति का कोई भी नुकसान प्रबंधन के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा।

प्रशिक्षित कर्मचारियों को चौबीसों घंटे उपलब्ध रहना चाहिए।

'समय पर पहुंचती मदद, तो बच सकती थी तीनों की जान'

एक छात्र ने बताया कि 30-35 लोग पुस्तकालय में थे। जैसे ही पानी अंदर तेजी से भरने लगा सब बाहर भागने लगे। इसी बीच बिजली भी कट गई। अंदर पूरा अंधेरा हो गया था। सब अपने-अपने फोन का टार्च जलाए हुए थे। समय बहुत कम था और छात्र ज्यादा। पानी अंदर कमरे में बढ़ता ही जा रहा था। आठ से दस मिनट के अंदर पूरे बेसमेंट में पानी भर गया।

नई दिल्ली। मैं शाम को राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बने पुस्तकालय में पढ़ाई के लिए गया। वहां पहले से ही 15-20 अन्य छात्र मौजूद थे जो पढ़ाई कर रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहां बैठे किसी छात्र ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वर्षा का पानी अंदर आ जाएगा। ये कहना था बेसमेंट में भरे पानी से जान बचा कर भागे छात्र ह्रदेश का।

एक अन्य छात्रा ने बताया कि सभी छात्र अंदर ही बैठे थे कि तभी देखा अंदर बेसमेंट में पानी आ रहा है। कुछ ही सेकेंड में अचानक से पानी का इतना जोर का सैलाब आया कि कांच का बायोमीट्रिक गेट किनारे से टूट कर पानी तेजी से अंदर आने लगा। इसमें नाले का पानी भी अंदर आ रहा था। पानी भरने से बायोमीट्रिक भी काम नहीं कर रहा था। सब मदद के लिए चिल्लाने लगे।

बहुत भयानक मंजर था: प्रत्यक्षदर्शी छात्रा

उन्होंने कहा कि हम लोग ऊपर सीढ़ी की तरफ भागने लगे लेकिन वहां पर गंदा पानी इतनी वेग से पानी नीचे आ रहा था कि सीधे मुंह पर लग रहा था। बहुत भयानक मंजर था। मेरे कुछ दोस्त पीछे ही थे। हमें लगा सब भाग कर जल्दी-जल्दी ऊपर आ जाएंगे।

एक अन्य छात्र ने बताया कि 30-35 लोग पुस्तकालय में थे। जैसे ही पानी अंदर तेजी से भरने लगा सब बाहर भागने लगे। इसी बीच बिजली भी कट गई। अंदर पूरा अंधेरा हो गया था। सब अपने-अपने फोन का टार्च जलाए हुए थे। समय बहुत कम था और छात्र ज्यादा। पानी अंदर कमरे में बढ़ता ही जा रहा था। लगा कि पानी चार फुट तक है तो कुछ छात्र कुर्सी में चढ़ गए और कुछ मेजों में। लेकिन आठ से दस मिनट के अंदर पूरे बेसमेंट में 12 फुट ऊपर तक गंदा पानी भर गया था।

दोस्तों ने रस्सियां फेंककर बचाई जान: प्रत्यक्षदर्शी छात्र

उन्होंने कहा कि मेरी नजर केवल सीढ़ियों की ओर ही थी। मैं बस इसी कोशिश में था कि किसी तरह वहां तक पहुंच जाऊं। मेरे दोस्तों ने ऊपर से रस्सियां और पानी का पाइप फेंकना शुरू किया। बहुत कोशिश के बाद पानी का पाइप पकड़ में आया और फिर दोस्तों ने ऊपर की ओर खींचा।

एक अन्य छात्र ने बताया कि जब वो भरे पानी से बच कर बाहर आया तो उसने बाहर खड़े लोगों को बताया कि अंदर अभी भी काफी लोग है। शाम 6 बजकर 40 मिनट हुए थे। आनन-फानन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस को मदद के लिए कॉल कर के मदद मांगी।

दिल्ली पुलिस रात 9 बजे पहुंची: प्रत्यक्षदर्शी छात्र

छात्रों ने आरोप लगाया कि वो लोग कोचिंग के कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने रस्सियों व पानी के पाइप के सहारे एक दूसरे की मदद कर बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से बचाव के लिए कोई नहीं आया। आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस रात करीब नौ बजे पहुंची थी। गुस्साएं छात्रों ने कहा कि अगर समय पर मदद मिल जाती तो सभी की जान बच सकती थी। कोचिंग के सामने जूस की ठेली लगाने वाले रमेश ने बताया कि सड़क पर इतना पानी भर गया था कि उनकी ठेली तक डूब गई थी। स्थिति खराब देख उन्होंने सुरक्षा गार्ड को सूचित किया और फिर सभी बेसमेंट से बच्चों को बचाने में जुट गए। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय में एक सुरक्षा गार्ड का बेटा भी उस समय पढ़ रहा था।

श्रीराम इंस्टीटयूट में ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। *रोहिणी के सैक्टर-5, विजय विहार फेज-1 स्थित श्रीराम एजूकेशन एंड वेल्फेयर ट्रस्ट एवं लायंस क्लब दिल्ली के संयुक्त सौजन्य से श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एंड वोकेशनल स्टडीज भवन में एक दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैंकडों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से इस भाग में 38 लोगों द्वारा अपना स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। रक्त कलेक्शन पीतम पुरा ब्लड बैंक द्वारा लिया गया। इस ब्लड बैंक शिविर कार्यक्रम में विजय विहार वार्ड-24 की निगम पार्षद पुष्पा सुरेंद्र सौलंकी, रोहिणी वार्ड-51 के निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा, खाटू श्याम परिवार कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद थे।कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में विजय विहार फेज-1(RWA), और आयोजन कर्ता इंस्टिट्यूट के चेयरमैन ललित गोयल ने उपस्थित सभी अतिथियों, लायंस क्लब नोर्थ वेस्ट, श्री खाटू श्याम परिवार नोर्थ वेस्ट समेत दोनों पार्षद और रक्तदान करने वालो का आभार जताया।*

कांवड़ लाने की तैयारियां कर रहा था युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में गर्दन आने से गई जान

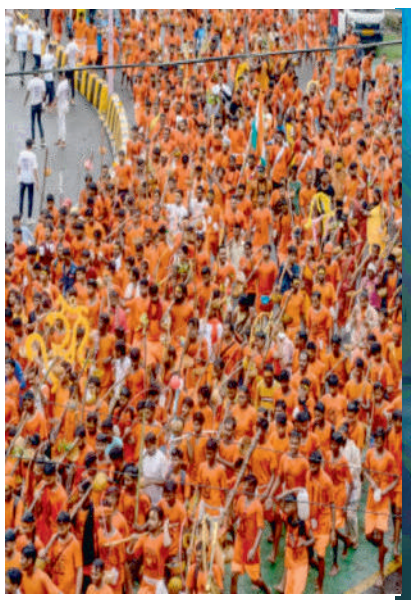

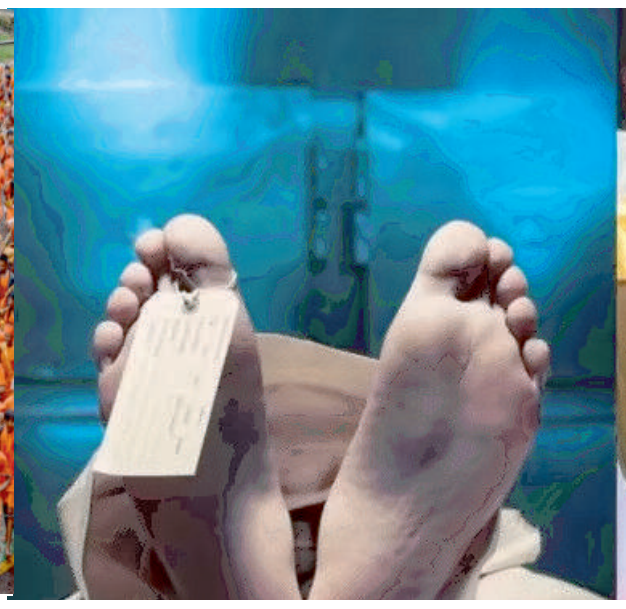

परिवहन विशेष न्यूज

कांवड़ लाने की तैयारी कर रहे एक कांवड़िए की करंट लगने से मौत हो गई। वह दोस्तों के साथ डाक कांवड़ लेने जाने की तैयारी कर रहा था। डाक कावंड़ लाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में म्यूजिक सिस्टम लगवाया था। 11 हजार की लाइन के तार नीचे लटके थे। वहां से ट्रैक्टर-ट्रॉली को निकलने में दिक्कत हो रही थी।

ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के कुलेसरा गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अपने दोस्तों के साथ डाक कांवड़ लेने जाने की तैयारी कर रहा था।

मूलरूप से बदायूं निवासी रमेश (26) अपने परिवार के साथ कुलेसरा गांव में किराये पर रहता था। वह अपने भाइयों के साथ सटरिंग लगाने का काम करता था। पिछले साल की तरह बार भी वह अपने भाई व दोस्तों के साथ डाक कांवड़ लाने की तैयारी कर रहा था।

कांवड़ लेने जा रहा था रमेश

डाक कावंड़ लाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में म्यूजिक सिस्टम लगवाया था। मृतक रमेश के बड़े भाई सूरज ने बताया कि रविवार दोपहर करीब ढाई बजे वो घर से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पुश्ते पर जा रहा था। वहां से सभी को एक साथ निकलना था।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई गर्दन

उसके साथ रमेश से बड़ा भाई पप्पू व दो अन्य युवक थे। बारात घर के समीप 11 हजार की लाइन के तार नीचे लटके थे। वहां से ट्रैक्टर-ट्रॉली को निकलने में दिक्कत हो रही थी। म्यूजिक सिस्टम के ऊपर चढ़कर रमेश डंडे से तार ऊपर करने लगा। तभी तार उसकी गर्दन पर आ लगा।

इससे वह झुलस गया। पप्पू को भी करंट लगा और वह नीचे गिर गया। साथ के युवकों ने रमेश को तार से हटाया। गंभीर हालत में उसे नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस का कहना है कि मृतक कांवड़ियां नहीं था। वो कांवड़ लेने जाने की तैयारी कर रहा था। पीड़ित स्वजन ने मामले की शिकायत नहीं की है।

मुंबई एक्सप्रेस-वे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार में लगी आग, बाल-बाल बचे वाहन सवार

गुरुग्राम के सोहना सदर थाना क्षेत्र में सोहना-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लोहटकी के पास डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई और आग लग गई। बताया जाता है कि आग लगने से पहले ही कार सवार सभी पांच लोगों को निकाल लिया गया। घटना शाम करीब छह बजे की बताई जा रही है। एक दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

गुरुग्राम। सोहना सदर थाना क्षेत्र में सोहना-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लोहटकी के पास डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई और आग लग गई। बताया जाता है कि आग लगने से पहले ही कार सवार सभी पांच लोगों को निकाल लिया गया। घटना शाम करीब छह बजे की बताई जा रही है। एक दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

सोहना पुलिस के अनुसार फिरोजपुर झिरका निवासी अशोक कुमार टाटा नेक्सान कार से परिवार सहित गुरुग्राम जा रहे थे। रास्ते में सोहना-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गांव लोहटकी के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पास से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने तुरंत ही कार सवार लोगों को बाहर निकाला।

एयरबैग खुलने से बाल-बाल बचे

कार में एक बच्चा और महिला सहित पांच लोग सवार थे। टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए। इससे लोग बाल-बाल बच गए। लोगों के बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद ही कार में आग लग गई। सूचना के बाद सोहना सदर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।

नोएडा में AVRWA ने सिल्वर जुबली कारगिल विजय दिवस समारोह का किया आयोजन

एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (AVRWA) ने गर्व के साथ कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली मनाने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत की कारगिल युद्ध में विजयी 25वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए था जिसमें हमारे बहादुर सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित किया गया। शाम का कार्यक्रम कारगिल के नायकों को समर्पित था।

नोएडा। एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (AVRWA) ने गर्व के साथ कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली मनाने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत की कारगिल युद्ध में विजयी 25वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए था, जिसमें हमारे बहादुर सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित किया गया।

शाम का कार्यक्रम कारगिल के नायकों को समर्पित था, जहां क्षेत्र को सुंदर रोशनी और देशभक्ति से सजाया गया था। एक अनोखा सेल्फी बूथ बनाया गया था, जो सशस्त्र बलों की शैली में डिजाइन किया गया था। लोगों ने इसके साथ फोटो लेकर यादगार क्षणों को कैद करने की अनुमति दी। इससे समारोह में गर्व और यादें जुड़ गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई संगीतमय प्रस्तुतियां शामिल थीं, जो भारतीय सशस्त्र बलों की अटूट भावना को सलाम करती थीं। मधुर धुनों ने देशभक्ति और श्रद्धा की भावना को जागृत किया, क्योंकि उपस्थित लोगों ने देशभक्ति गीतों में शामिल होकर गाया।

शाम के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कारगिल शहीदों के परिवारों की उपस्थिति थी। उनकी भागीदारी ने गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना को जोड़ा, जिससे सभी को हमारे सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाई गई।

कर्नल आईपी सिंह ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और कारगिल नायकों की बहादुरी और उनके परिवारों के अटूट समर्थन की सराहना की। अपने संबोधन में कर्नल सिंह ने दिन के महत्व और हमारे राष्ट्र के रक्षकों को याद करने और सम्मानित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि यह समारोह न केवल एक ऐतिहासिक विजय की याद है बल्कि हमारे बहादुर सैनिकों की भावना और बलिदानों को श्रद्धांजलि है। उनकी विरासत का सम्मान करना और युवा पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है।

यह कार्यक्रम बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें समुदाय ने सामूहिक रूप से गर्व और कृतज्ञता की भावना व्यक्त की।

दादरी क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी, 25 करोड़ से प्यावली में बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय

परिवहन विशेष न्यूज

जिला प्रशासन ने विद्यालय के लिए जमीन चिह्नित कर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार निजी व सरकारी स्कूलों के बीच की खाई पाटने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष सुविधाओं वाले इंटर कॉलेज बना रही है। यह स्कूल प्रदेश में बदलती शिक्षा व्यवस्था के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे।

ग्रेटर नोएडा। दादरी क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए खुशखबरी है। क्षेत्र के प्यावली गांव में 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनने जा रहा है।

लड़कियों के सपनों को मिलेगी उड़ान

इससे क्षेत्र लगभग 30 गांवों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। क्षेत्र में अभी तक कोई इंटर कालेज नहीं होने से छात्रों को 15 से 20 किमी दूर दादरी शहर जाना पड़ता था। दूरी के कारण अभिभावक खासकर लड़कियों की पढ़ाई भी छुड़वा देते थे, लेकिन अब विद्यालय निर्माण के बाद लड़कियों के सपनों को भी उड़ान मिल सकेगी। आगे इनकी तर्ज पर दूसरे विद्यालय भी तैयार किए जाएंगे।

मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण से तीस गांवों के बच्चों को फायदा होगा। उन्हें शिक्षा के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। खासकर लड़कियों को शिक्षा जारी रखने का मौका मिलेगा। मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए किया गया प्रयास सफल रहा है। - तेजपाल नागर, विधायक दादरी

यह होंगी विद्यालय में सुविधाएं

जनपद में पहला मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय दादरी में बनने जा रहा है।

विद्यालय को मल्टी स्टोरी बनाया जाएगा।

प्री प्राइमरी से 12वीं तक के छात्रों के लिए करीब 30 से अधिक कक्षाएं होगी।

इसके साथ ही खेल का मैदान बनाया जाएगा।

रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान के साथ ही एआइ की लैब बनाई जाएगी।

वाईफाई और ऑनलाइन सीसीटीवी मॉनिटरिंग की सुविधा होगी।

साफ-सफाई के लिए कर्मचारी और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगे।

एक मल्टीपर्पज रूम होगा, रेनवाटर कलेक्शन सिस्टम, सोलर पैनल भी स्कूल में लगाए जाएंगे।

आरओ वाटर प्लांट, हाथ धोने की जगह भी बनाई जाएगी। मिड-डे मील मिलेगा और इसके लिए डायनिंग हाल भी होगा।

इन गांवों के बच्चों को होगा फायदा

प्यावली के साथ-साथ आकलपुर, ऊंचा अमीरपुर, बिसाहड़ा, चौना, जैतवारपुर, रसूलपुर, ततारपुर, पटारी, नरौली, सीदीपुर के साथ 23 अन्य गांवों के बच्चों को इसका फायदा होगा। इसके साथ ही हापुड़ जनपद के गांव नंगला के बच्चों को भी हाईटेक विद्यालय में प्रवेश मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए प्यावली में करीब तीन एकड़ जमीन मिल गई है। यह विद्यालय हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। जल्द बजट जारी होते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जनपद का यह पहला विद्यालय होगा। जहां प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के बालक और बालिका पढ़ सकेंगे। - राहुल पंवार, बेसिक शिक्षा अधिकारी

किसान आंदोलन की समाधान राहें बातचीत से ही खुलेगी

ललित गर्ग

केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाई-वे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत तो इस समस्या का समाधान नहीं है।

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विकसित भारत लिये रोजगार, महंगाई नियंत्रण, कृषि, महिला-युवा विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये पहली बार सकारात्मक सोच सामने आयी है। बावजूद इसके विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं। सभी क्षेत्रों के लिये न्यायसंगत एवं विकास योजनाओं के बावजूद विरोध होना अतिश्योक्तिपूर्ण है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसी तरह की घोषणा न करने के मुद्दे हैं। विपक्षी दल किसान आन्दोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिये भी लग रहा है कि बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। संसद सत्र जारी है, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, एक बार फिर किसान आन्दोलन के उग्र से उग्रतर होने की संभावनाएं हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान-आन्दोलन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा से सटे शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का औचित्यपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम है कि एक 'तटस्थ मध्यस्थ' की आवश्यकता है जो सरकार और किसानों के बीच विश्वास कायम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। प्रश्न है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल न्यायालय के इस महत्वपूर्ण सुझाव को आकार देने की बजाय किसान-आन्दोलन को उग्र करने की मंशा रखते हुए अराजक माहौल ही क्यों बनाना चाहते है? क्यों अव्यवस्था फैलाने चाहते हैं? निश्चित ही शंभू बॉर्डर खोले जाने पर कानून-व्यवस्था को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह बात सही है कि शंभू बॉर्डर खोले जाने से आंदोलनरत किसानों के दिल्ली कूच की राह खुल सकती है। आंदोलनरत किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब भी सीमाएं खुलेंगी, किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाई-वे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत तो इस समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति के जरिए बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन दोनों पक्षों को ही आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकालने की पहल करनी होगी। किसान आंदोलन के उग्र रूप को भी यह देश देख चुका है, भारी नुकसान भी हुआ है। किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं और इनकी आड़ में होने वाली राजनीति अपनी जगह। वैसे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर समिति के गठन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार पहले ही दे चुकी है। यह बड़ा सच है कि बात करने से ही बात बनती है। बातचीत की हर संभावना का स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी आंदोलन का लंबे वक्त तक जारी रहना सचमुच चिंताजनक है। ऐसे आन्दोलन को उग्र करने की विपक्षी दलों की मानसिकता भी संदेहों एवं अविश्वासों से घिरी है। अच्छा हो कि विपक्षी दल एवं नेता प्रचार पाने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय बजट में कृषि क्षेत्र के लिये किये गये बड़े ऐलानों पर गौर करें। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मौसम में बदलाव को बरदाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट को भी बढ़ाया गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों एवं कृषि को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। कोई न कोई बहाना चाहिए विरोध का, अब किसान-आन्दोलन के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में देश का कितना नुकसान होगा, कहा नहीं जा सकता। जबकि भाजपा सरकार द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि में उत्पादकता, किसानों के हितों एवं कृषि की सुदृढ़ता को बढ़ाना बजट द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि बजट में जो नौ प्राथमिकताएं शामिल है, उनमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से खेती-किसानी की दशा-दिशा सुधरने की आस बढ़ी है। विभिन्न फसलों की प्रस्तावित 109 किस्मों से भी उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के विरुद्ध कवच का काम करेंगी। दलहन-तिलहन को प्राथमिकता, डिजिटल क्राप सर्वे के अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ एवं भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने जैसे उपाय उपज को पहुंचने वाले नुकसान को घटाने एवं कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। भले ही सरकार ने सीधे तौर पर बजट में किसानों की आय बढ़ाने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित न किए जाने से किसानों को निराशा हुई हो लेकिन बजट में तिलहन में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन केन्द्र विकसित करने और खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी जो सीधे तौर पर किसानों की आय भी बढ़ायेगा एवं उन्नत कृषि को प्रोत्साहन भी देगा।

असल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगें राजनीतिक मुद्दे बन गये हैं, जिनके चलते हो रहा आन्दोलन न केवल किसानों के बल्कि आम जनता के लिये भी परेशानी का सबब है। जबकि सरकार ने धान का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ा कर 2300 कर दिया है जो स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद थी की सरकार एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी। लेकिन बजट में इस तरह का कोई प्रावधान न होने से काफी निराशा हुई है। दुनिया भर के विकसित देश अनिवार्य रूप से किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदते हैं। लेकिन भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। विपक्षी दल किसानों के हित में आन्दोलन की बजाय बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े। स्तरीय विरोध हो, किसानों को गुमराह करने एवं उनका मनोबल कमजोर करने के लिये विपक्षी दल उजालों पर कालिख न पोते, इससे उन्हीं के हाथ काले होने की संभावनाएं है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज बढ़ाने वाले आविष्कार को मिला पेटेंट

परिवहन विशेष न्यूज

एक प्रमुख आविष्कार में, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज को बढ़ाने और उनकी समग्र लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, तिरुवनंतपुरम में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (सीईटी) के शोधकर्ताओं ने ईवी मोटर्स के नियंत्रण के लिए एक डिजिटल मॉड्यूलेशन योजना विकसित की है, जो वर्तमान में उपयोग में आने वाली एनालॉग योजना की जगह लेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन नियंत्रण के लिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन योजना के आविष्कार के लिए शोधकर्ताओं को केंद्र सरकार से पेटेंट मिला है।

इस नियंत्रण योजना का आविष्कार सीईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर बिजी जैकब तथा विभाग की शोध छात्रा जीश्मा मैरी पॉल ने किया था।

पल्स कोड मॉड्यूलेशन स्कीम पर आधारित आविष्कार की खासियत यह है कि यह ईवी के नियंत्रण के लिए पारंपरिक पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन की तुलना में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करता है। प्रदर्शन को अनुकूलित करने, दक्षता को अधिकतम करने और इस प्रकार ईवी की बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए मोटर का प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

बिजी ने बताया, ₹चूंकि नई-नई आविष्कृत मॉड्यूलेशन स्कीम प्रकृति में असंतत है, इसलिए स्विचिंग नुकसान कम हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल बिजली की बचत होती है और बैटरी की रेंज लंबी होती है।"

उन्होंने कहा कि ईवी मोटर में उनके आविष्कार को सफलतापूर्वक एकीकृत करने से बैटरी पर लोड 20% तक कम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ड्राइविंग रेंज बढ़ जाती है। वर्तमान में ईवी की सीमित ड्राइविंग रेंज कई संभावित खरीदारों को हतोत्साहित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है।

बिजी ने कहा, "यह आविष्कार पारंपरिक एनालॉग प्रणाली की तुलना में अधिक सरल है तथा इससे इलेक्ट्रिक वाहनों में नियंत्रकों की लागत भी कम हो जाएगी, जिससे उनकी कुल लागत कम हो जाएगी।"

अनुसंधान छह साल पहले शुरू हुआ था और पेटेंट के लिए आवेदन 2021 में प्रस्तुत किया गया था। शोधकर्ता अब अपने आविष्कार के औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए ईवी निर्माताओं के साथ गठजोड़ करने की उम्मीद कर रहे हैं।

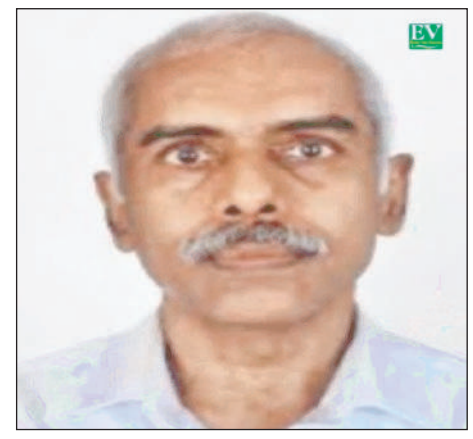

भारत में ईवी चार्जिंग अनुभव को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने इलेक्ट्रिकपे के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

सर्च दिग्गज गूगल ने ईवी चार्जिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भारतीय स्टार्टअप इलेक्ट्रिकपे के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग से भारत भर में गूगल मैप्स के उपयोगकर्ता चार्जिंग पॉइंट की वास्तविक समय उपलब्धता और स्थिति देख सकते हैं, जिससे बेहतर यात्रा योजना बनाने और रेंज की चिंता को कम करने में मदद मिलती है। यह सुविधा गूगल मैप्स और गूगल सर्च दोनों पर लाइव होगी और इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने की योजना है।

मई 2021 में अविनाश शर्मा और राघव रोहिला द्वारा सह-स्थापित इलेक्ट्रिकपे अपने

ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को भारत भर में चार्जिंग प्वाइंट से जोड़ता है, जिससे चार्जिंग और भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन की सुविधा मिलती है। बेंगलुरु स्थित कंपनी, जिसने ब्लूम वेंचर्स और अन्य से $8.29 मिलियन जुटाए हैं, बेंगलुरु में 25,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जर संचालित करती है, जो इसे शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाता है।

बाजार अनुसंधान परियोजनाएं भारत में 2030 तक 5 मिलियन से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होंगे। हाल ही में गूगल ने 1 अगस्त से भारत में डेवलपर्स के लिए गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म की कीमत में 70% की कटौती की घोषणा की, जिससे स्टार्टअप को ओला मैप्स जैसे स्थानीय विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के नियम को लेकर बनाए गए आसान

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने दो नए नियम बनाए हैं, इन नियमों के अनुसार राज्य के बिजली वितरण निगमों के सीएसआर फंड से 200 किलोवाट तक के लोड के लिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने में मदद मिलेगी। डिस्कॉम के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड में कमी होने पर राज्य की बिजली वितरण कंपनियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका में इसका दावा कर सकती हैं। इसके अलावा अब 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफ टॉप सोलर के लिए तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त को खत्म कर दिया गया है।

एचईआरसी के चेयरमैन नंद लाल शर्मा और सदस्य मुकेश गर्ग ने इस संबंध में जन सुनवाई की थी। उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इन नियमों को अधिसूचित किया गया, ये नियम पूरे हरियाणा में लागू हो गए हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल बनाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं की लंबे समय से मांग रही है।

इस मामले में 10 किलोवाट क्षमता तक की पूरी क्षमता वाली रूफटॉप सौर फोटो वोल्टेइक प्रणालियों के लिए आवेदन को तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के बिना स्वीकृत माना जाएगा और उपभोक्ता के स्वीकृत भार में कोई भी आवश्यक वृद्धि, आवश्यकतानुसार, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा यदि तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान इन विनियमों में निर्दिष्ट रूफटॉप सिस्टम क्षमता और उपलब्ध वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) लोडिंग के संबंध में आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन द्वारा आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को ईमेल / एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ई-रिक्शा के लिए आसान किस्तों पर करवाया जाएगा ऋण उपलब्ध : डीसी मोनिका गुप्ता

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ई-रिक्शा लेने के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए नारनौल की डीसी मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना तहत पहले महिलाओं को सरकार द्वारा फ्री में प्रशिक्षण देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाएगा। इसके बाद उन्हें बैंकों के माध्यम से ब्याज पर छुट देते हुए ई-रिक्शा लेने के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ के लिए वर्ष 2024-25 में 30 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि इस बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए बस स्टैंड के नजदीक नरूला होटल के पीछे स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय नारनौल में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।

डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपए से कम व महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर तीन वर्षो तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कम से कम आठवीं पास होना चाहिए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, आदि शामिल हैं। आवेदक आवेदन करने के लिए कार्यालय में सभी दस्तावेज की दो-दो फोटोकॉपी साथ लाएं।

भारत के लोग आज भी इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को लेकर हैं चिंतित: ज़फ़र इकबाल

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में वित्त वर्ष 2023-24 से इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में काफी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लोग विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड व्हीकल की ओर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि, ईवी की डिमांड भारत में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी अधिक कीमतों के चलते अभी भी लोग कहीं न कहीं खरीदने से कतरा रहे हैं। ऐसे में अब लोगों के मन एक सवाल उठ रहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोग कैसे अपनाएंगे और देश में इसका क्या भविष्य है। इस सवाल को लेकर ईवी ड्राइव द फ्यूचर ने ईवी एक्सपर्ट्स प्लग एन राइड के सीईओ ज़फ़र इकबाल से बातचीत की।

प्लग एन राइड के सीईओ ज़फ़र इकबाल ने भारत में इलेक्ट्रिक फ्यूचर के बारे में बात करते हुए ईवी ड्राइव द फ्यूचर को बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। भारत में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा हैं। देश में परिवहन क्रांति की जरूरत है, जो इलेक्ट्रिक वाहन लाने में पूरी तरह से सक्षम है। इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन के क्षेत्र में एक स्थायी परिवहन भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक और सार्वजनिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी, जो पर्यावरण और आर्थिक रूप से टिकाऊ हो।

ज़फ़र इकबाल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने और कार्बन के बढ़ते उत्सर्जनों को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन करके एक आशाजनक भविष्य देने की कोशिश की जा रही है। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, जो प्रदूषण रहित देश बनाने के अभियान में इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट कर रहा है।

उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से वह एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं। भारतीय कस्टमर अब स्थाई उपाय के रुप में ईवी वाहनों पर भरोसा करने लगे हैं। भारत में ईवी की बढ़ती बिक्री इस बात का प्रमाण है। भारत सरकार भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ईवी पहुंचाने की पहल कर रही है। निकट भविष्य में हम हरे-भरे और प्रदूषण रहित समाज की कल्पना कर सकते हैं।

'हम फंस गए हैं, आप न फंसें', आखिर आधे से ज्यादा ईवी मालिक दूसरों को क्यों दे रहे हैं ये सलाह

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहनों को फ्यूचर मोबिलिटी माना जा रहा है। सरकार भी इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर समेत दूसरे ईवी को बढ़ावा दे रही है। पिछले कुछ सालों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। लेकिन, हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला है कि ईवी खरीदने वाले आधे से ज्यादा लोग अपने फैसले से खुश नहीं हैं। अब वे फिर से आईसी इंजन यानी इंटरनल कम्बशन इंजन वाला वाहन खरीदना चाहते हैं। अब उन्हें लगता है कि डीजल, पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाला वाहन ही सही है। इस सर्वे में दिल्ली व एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु के 500 इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को शामिल किया गया था।

यह सर्वे पार्क प्लस द्वारा कराया गया था। सर्वे में शामिल 51 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें ईवी खरीदने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। ईवी में कई तरह की दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन न होने, नियमित रखरखाव में दिक्कत और बेहद कम रीसेल वैल्यू की वजह से ईवी मालिकों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना फायदे का सौदा नहीं है।

सर्वेक्षण के अनुसार 88% इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए सुलभ, सुरक्षित और कार्यात्मक चार्जिंग स्टेशन ढूँढना सबसे बड़ी चिंता थी। भारत में 20,000 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन होने के बावजूद, ईवी मालिकों को लगा कि इन स्टेशनों की दृश्यता बहुत कम है और उन्हें ढूँढना एक मुश्किल काम है। ईवी मालिक 50 किलोमीटर से कम की सीमित दूरी वाली छोटी शहरी यात्राएँ पसंद करते हैं।

सर्वे में शामिल 73 प्रतिशत ईवी मालिकों ने कहा कि उनकी ईवी कारें ₹ब्लैक बॉक्स₹ की तरह हैं, जिन्हें वे समझ नहीं पाते। रखरखाव एक बड़ी समस्या है। स्थानीय मैकेनिक छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और वाहन को कंपनी के अधिकृत डीलर के पास ले जाना पड़ता है। इसके अलावा मरम्मत की लागत के बारे में भी कोई पारदर्शिता नहीं है।

ईवी वाहनों की रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है। किसी वाहन की कीमत तय करने का कोई तार्किक तरीका बना ही नहीं है। यही वजह है कि अगर ईवी को बेचना भी पड़े तो उसकी कीमत बहुत कम मिलती है। वहीं, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी वाहन की रीसेल वैल्यू का बेहतर तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। रीसेल वैल्यू की गणना वाहन की स्थिति और अब तक चली किलोमीटर के आधार पर की जाती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में हलचल मचाने को तैयार है जियो

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले कुछ सालों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग काफी बढ़ गई है। इनमें से कई वाहन एडवांस तकनीक से लैस हैं और इनमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सपोर्ट भी है। यूजर्स की जरूरतों को समझते हुए जियो ने स्मार्ट मॉड्यूल और 4G एंड्रॉयड क्लस्टर लॉन्च किए हैं।

जियोथिंग्स ने दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 4जी एंड्रॉयड क्लस्टर पेश किया है। यह मेड इन इंडिया डिजिटल क्लस्टर है। जियो के इस कदम को ईवी सेक्टर में उसके प्रवेश के तौर पर देखा जा रहा है। जियो के स्मार्ट मॉड्यूल और 4जी एंड्रॉयड क्लस्टर दोपहिया वाहनों में लगाए जाते हैं। इसके लिए जियो ने मीडियाटेक के साथ करार किया है। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके जियो ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ओला और एथर जैसी स्थापित कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है।

जियो का 4G एंड्रॉयड क्लस्टर मेड इन इंडिया ऑटोमोटिव ऐप सूट है। इसकी मदद से जियो ग्राहक JioSaavn, JioXploR, Jio Voice Assistant जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। जियो थिंग्स AvniOS स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर पर आधारित है। जियो का यह स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर रियल टाइम डेटा एनालिसिस करता है। इसमें वाहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक अनूठा इंटरफेस है।

डिजिटल क्लस्टर को इलेक्ट्रिक वाहनों का चेहरा कहा जा सकता है, जहां आपको वाहन की स्पीड, गियर समेत तमाम जानकारी मिलती है। स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर इससे एक कदम आगे हैं। इसमें यूजर्स को वॉयस कॉलिंग के साथ 4जी कनेक्टिविटी और मैप्स की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही म्यूजिक और तमाम तरह की डिजिटल सुविधाएं मिलती हैं। आज के समय में स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर की डिमांड बढ़ गई है, जिन्हें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में लगाया जाता है।

आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां से कहां पहुंचे?

विजय गर्ग

भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की शुरुआत एक तरह से तब हुई, जब 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। पहले का फोकस पाठ्यक्रमों को दुरुस्त करने, शिक्षा के माध्यम और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट और टीचरों की व्यवस्था पर फोकस करना था।

अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रखने की नीति अपना रखी थी। उन्हें सिर्फ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से वास्ता था, जिससे उनका काम चल जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। बाकी आम भारतीय साक्षर हों, पढ़-लिख जाएं,तरक्की करें, इस झमेले में वे कभी नहीं पड़े। अंग्रेजों के जमाने के जो कॉलेज और स्कूल थे, वहां की शिक्षा की गुणवत्ता जरूर अच्छी थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। अंग्रेजों ने देश में जिस तरह से रेलवे लाइन का जाल बिछाया, उस तरह से शिक्षा को बेहतर करने के बारे में कभी ज्यादा सोचा ही नहीं; और जो शिक्षा नीति अपनाई, वह सिर्फ उनके फायदे हिसाब से तैयार की गई थी। लिहाजा आजादी के बाद इसपर शुरुआत से काम हुआ और आज हमारी शिक्षा व्यवस्था विकसित देशों को टक्कर देने की स्थिति में आने लगी है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने रणनीति भी वैसी ही बनाई है।

शिक्षा क्षेत्र में शुरुआत

भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की शुरुआत एक तरह से तब हुई, जब 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। पहले का फोकस पाठ्यक्रमों को दुरुस्त करने, शिक्षा के माध्यम और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट और टीचरों की व्यवस्था पर फोकस करना था। जबकि, दूसरे को स्कूल और माध्यमिक शिक्षा और शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर सुझाव देना था। इसी दौर में 1945 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी)और 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) का गठन हुआ। पहली संस्था का काम तकनीकी शिक्षा पर सलाह देना, दूसरी का विश्वविद्यालयों को वित्तीय सलाह और अनुदान आवंटित करना और तीसरी का शिक्षण सामग्री और उसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करवाने पर ध्यान देना है।

शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण नीतियां और सुधार

1964-66 में आकर शिक्षा आयोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को लेकर कई अहम सुझाव दिए। भारत में शिक्षा के विकास के मकसद से सुझाव देने के लिए पहले आयोगों में से एक कोठारी कमीशन था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इस नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा में तीन भाषाओं वाली शिक्षा पर जोर दिया गया- अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। 18 साल बाद 1986 में इसी शिक्षा नीति में संशोधन की गई। अब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी पर फोकस हुआ। इसके अलावा इसमें महिला और अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसी दौरान ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड भी लॉन्च किया गया। 1990 के दशक में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए मिड-डे मील जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अभियान का अप्रत्याशित लाभ दिखाई दिया। फिर सर्व शिक्षा अभियान और पढ़े भारत-बढ़े भारत ने भी प्राथमिक शिक्षा में काफी योगदान दिया। 2009 में तो 'शिक्षा का अधिकार' देकर इसे मौलिक अधिकार ही बना दिया गया, जिससे हर बच्चे को पढ़ने का हक मिला। 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है और अब मानव संसाधन और विकास मंत्राल का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है तो इसी नीति पर सरकार का जोर है। इस नीति के तहत शिक्षा के डिजिटलीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस नीति के तहत स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई पर फोकस रहने के साथ 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है।

साक्षरता दर

आगे हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, वह बीते 77 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों का परिणाम है, जो आंखें खोल देने वाला है। मसलन, देश की आजादी के समय हमारी साक्षरता की दर जो सिर्फ 12% थी, 2022 में उसके 80% तक हो जाने का अनुमान है। स्वतंत्रता के तीन साल बाद यानी 1951 में ही यह आंकड़ा 18.3% हो चुका था और 2018 में यह 74.4% था। सबसे क्रांतिकारी बदलाव महिला साक्षरता दर में देखने को मिली है। 1951 में यह सिर्फ 8.9% थी, जो कि 2018 में 65.8% हो चुकी थी।

लैंगिक समानता

महिला साक्षरता दर में जो क्रांतिकारी बदलाव नजर आया है, उसकी वजह ये है कि 7-8 दशक पहले देश में महिलाओं की पढ़ाई को अहमियत नहीं थी। ज्यादातर लोग बेटियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। लेकिन, अब हालात ठीक उलट चुके हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक स्कूली शिक्षा में लड़कियां, लड़कों को पीछे छोड़ चुकी हैं। पहली से आठवीं तक की कक्षा में लड़कों के मुकाबले ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। पहली से पांचवीं तक की कक्षा में प्रत्येक लड़के के मुकाबले 1.02 लड़कियां पढ़ रही हैं। 1951 में इस श्रेणी में लड़कियों का अनुपात मात्र 0.41 था। इसी तरह छठी से आठवीं तक की कक्षा में प्रत्येक लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 1.01 है।

स्कूल-कॉलेजों की संख्या

साल 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में स्कूलों की संख्या 15 लाख थे। जबकि, आजादी के समय देश में सिर्फ 1.4 लाख स्कूल हुआ करते थे। इसी तरह आजादी के बाद कॉलेजों की संख्या में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1950-51 में देशभर में सिर्फ 578 कॉलेज होने का डेटा है। जबकि, आज की तारीख में 42,343 कॉलेजों के आंकड़े हैं।

विश्वविद्यालयों की संख्या

उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ। आज की तारीख में देश में अनेकों निजी विश्वविद्यालय भी मौजूद हैं। कई तो देश के बाहर के विद्यार्थियों को भी शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि, वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास काफी प्राचीन और प्रतिष्ठित माना जाता था। लेकिन, करीब 800 वर्षों की गुलामी ने देश को शिक्षा के क्षेत्र में लगभग खोखला करके रख दिया था। आजादी के समय देश में सिर्फ 27 विश्वविद्यालय थे, जो आज की तारीख में 2,043 हो चुके हैं। वैसे अंग्रेजों के जमाने के जो शिक्षण संस्थान थे, उनकी गुणवत्ता में कमी नहीं थी, लेकिन उसका मकसद भारतीय नहीं, अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों को पूरा करना ज्यादा था।

उच्च प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और मेडिकल शिक्षण संस्थान

भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाने के लिहाज से आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों जैसे संस्थानों का बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत की पहला आईआईटी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में 1951 में स्थापित हुई थी। 15 सितंबर, 1956 को संसद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (खड़गपुर) ऐक्ट पास हुआ। तत्कालीन पीएम जवाहर लाल नेहरू ने आईआईटी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया था। आज देश में कुल 23 आईआईटी हैं। देश में आईआईएम की शुरुआत 1961 से हुआ और उस साल 'कलकत्ता' और अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई। आज देश में इनकी संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एम्स की प्रतिष्ठा का कोई तोड़ नहीं है। दिल्ली में एम्स की शुरुआत 1956 में हुई थी। आज देश में कुल 19 एम्स काम कर रहे हैं और 4 पाइपलाइन में हैं। इसी तरह 1951 में देश में सिर्फ 28 मेडिकल कॉलेज थे। इनकी संख्या अब बढ़कर 1000 से ज्यादा हो चुकी है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य
शैक्षिक स्तंभकार मलोट

संपादक की कलम से

नशों से समाप्त होती आज की जवानी

शराब से लेकर चरस, अफीम, गांजा आदि का नशा करने की आदत समूचे विश्व में व्याप्त है परन्तु अलग-अलग देशों में और क्षेत्रों में इसकी मात्रा में भिन्नता है। भारत में भी नशे का संसार काफी फैला हुआ है। परन्तु पंजाब में तो नशे ने सीमाएं पार कर रखी हैं।

शराब से लेकर चरस, अफीम, गांजा आदि का नशा करने की आदत समूचे विश्व में व्याप्त है परन्तु अलग-अलग देशों में और क्षेत्रों में इसकी मात्रा में भिन्नता है। भारत में भी नशे का संसार काफी फैला हुआ है। परन्तु पंजाब में तो नशे ने सीमाएं पार कर रखी हैं। पंजाब में नशे को लेकर कुछ ही वर्ष पूर्व एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था 'उड़ता पंजाब'। पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर कंटीली तारें कई दशकों से जीरो लाइन पर बनने के स्थान पर भारत की सीमाओं के अंदर बांधी गई हैं, कहीं-कहीं पर तो ये तारें जीरो लाइन से एक किलोमीटर से भी अधिक भारत की तरफ देखी जाती हैं। यदि इन तारों को जीरो लाइन पर ही लगा दिया जाए तो नशीले पदार्थों की तस्करी भी रोकी जा सकती है।

पाकिस्तान से आने वाला नशा एक और मायने में बड़ा भयंकर है जिसे 'चिट्टा' कहा जाता है। यह 'चिट्टा' वास्तव में एक सिंथैटिक नशा है जो अत्यन्त हानिकारक रासायनिक पदार्थों से बनता है। इसका नशा शरीर के अंदर सारे तंत्रों को तीव्र गति से हानि पहुंचाता है। इन्हीं कारणों से पंजाब का नशा सारी दुनिया में फैले नशे की समस्या से अधिक गम्भीर है। नशे के कारण व्यक्ति सबसे पहले तो अपने घर का ही धन बर्बाद करता है। धन पर रोक लगती है तो वह सबसे पहले अपने घर में ही चोरियां शुरू करता है। इसके बाद नशे का प्रभाव समाज को भी झेलना पड़ता है क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति समाज में भी अपराध का खिलौना जल्दी बन जाता है। नशे के कारण व्यक्ति किसी व्यापार या नौकरी के लायक भी नहीं रहता। यह बेरोजगारी और अपराध तीसरे स्तर पर सरकार के लिए भी एक समस्या बन जाते हैं।

पुलिस, प्रशासन, समाजसेवा आदि जैसे सरकारी विभागों को सामूहिक रूप से एक नीति का निर्माण करना चाहिए कि जितना संघर्ष उन्हें नशा करने वाले व्यक्ति के अपराधों के प्रबंधन में करना पड़ता है, उससे कम प्रयास से नशे के वितरण प्रणाली को ही क्यों न समाप्त किया जाए। इसके लिए सरकारी स्तर पर एक मजबूत और लक्ष्यबद्ध इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। नशे की आदत डालने के बाद हमारे समाज को जितना संघर्ष करना पड़ता है, यदि नशे के विरुद्ध चेतावनी देने के प्रयास छोटी अवस्था के बच्चों में ही पूरी चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रारम्भ कर दिए जाएं तो इसके बड़े सुंदर परिणाम निकल सकते हैं। इसके लिए स्कूलों के अध्यापकों और धार्मिक स्थलों के विद्वानों को विशेष प्रयास प्रारम्भ करने चाहिएं। उससे भी पहले ये प्रयास घरों में ही अपने बच्चों की चेतना जागृत करने के लिए माता-पिता तथा घर के अन्य वृद्धजनों के द्वारा प्रारंभ कर दिए जाने चाहिएं।

सामाजिक संस्थाएं घर-घर अभियान चलाकर छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के माध्यम से तथा वार्तालाप के माध्यम से छोटे और युवा होते बच्चों की नशा के विरुद्ध चेतना जागृत करें। मैं स्वयं जब भी किसी शिक्षण संस्थान में जाता हूं तो अपने उद्बोधन में पर्यावरण सुरक्षा, माता-पिता की सेवा और नैतिकता की अनेकों बातों के बीच नशों के विरुद्ध अवश्य ही चर्चा करता हूं और बच्चों से भविष्य में नशा न करने का संकल्प करवाता हूं। बच्चों पर स्कूलों और धर्मस्थलों से मिली शिक्षा की गहरी छाप पड़ती है। इसलिए हम सबको मिलकर नशों के विरुद्ध चेतना को अपने बच्चों की शिक्षा का अंग बना देना चाहिए, नहीं तो इन नशों के कारण हमारे समाज की जवानी पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। स्कूलों में बच्चों को लेकर नशे की हानियों के संबंध में डिबेट करवाई जाए, चित्र प्रतियोगिता करवाई जाए, बच्चों के घरों के अनुभवों पर उनके विचार सुने जाएं, बच्चों की गली-गली रैलियां निकाली जाएं और बच्चों को ऐसे अभियानों में खुलकर प्रोत्साहित किया जाए तो आज दिखाई देने में यह छोटा-सा प्रयास कुछ ही वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदल सकता है। बच्चे खुद तो प्रेरित होंगे ही बल्कि घर जाकर अपने वृद्धजनों को भी शराब के विरुद्ध सचेत करने का कार्य करते रहेंगे।

चिंतन

भारत तो स्वतंत्र है पर हमारी शिक्षा नहीं : विजय गर्ग

असल में हमारी आकांक्षाओं और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तब नजर आता है, जब हम स्कूलों की ओर देखते हैं। पिछले 77 सालों से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक स्वतंत्र सोच, आत्मविश्वास और इनोवेटिव भारतीय की तरह बड़े हों। लेकिन हमारे शिक्षा तंत्र ने वह सबकुछ किया है, जिससे उन्हें दबा हुआ और अधिकारहीन रखा जाए। यह दुखद है कि साल-दर-साल अभिभावकों को बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इनमें अधिकतर को मायूसी ही मिलती है, क्योंकि अच्छे स्कूलों में पर्याप्त सीटें नहीं हैं। शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट (एएसईआर) में हर बार यह बुरी खबर आती है कि कक्षा पांच के आधे से भी कम बच्चे ही एक पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं या कक्षा दो की किताब से गणित का सवाल हल कर सकते हैं। कुछ राज्यों में 10% से भी कम शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर पाते हैं। यूपी और बिहार में तो चार में से तीन शिक्षक पांचवीं की किताब से प्रतिशत का सवाल नहीं कर सकते। इसकी वजह अच्छे स्कूलों की कमी है। अभिभावकों को अपने बच्चे निजी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2015 के बीच सरकारी स्कूलों में नामांकन 1.1 करोड़ कम हुआ, इसके विपरीत निजी स्कूल में 1.6 करोड़ बढ़ा। इस ट्रेंड के आधार पर 2020 में देश में 1,30,000 अतिरिक्त निजी स्कूलों की जरूरत है, लेकिन वे नहीं खुल रहे हैं। क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला यह कि किसी ईमानदार के लिए स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए राज्य के अनुसार 30 से 45 अनुमतियों की जरूरत होती है और इनमें से अधिकांश के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। सबसे अधिक रिश्वत स्कूल बोर्ड से मान्यता हेतु असेंशियलिटी सर्टिफिकेट (यह साबित करना कि स्कूल की जरूरत है) के लिए देनी होती है। इस कमी की दूसरी वजह फीस पर नियंत्रण है। समस्या शुरू होती है शिक्षा का अधिकार कानून से। जब सरकार को लगा कि सरकारी स्कूल विफल हो रहे हैं तो उसने निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें गरीबों के लिए आरक्षित करने को कहा। यह एक अच्छा विचार था, लेकिन इसे खराब तरीके से लागू किया गया। क्योंकि सरकार निजी स्कूलों को इन आरक्षित सीटों के बदले ठीक से मुआवजा नहीं दे सकी, जिसकी वजह से फीस देने वाले 75 फीसदी बच्चों पर बोझ बढ़ा। इसका अभिभावकों ने विरोध किया। कई राज्यों ने फीस पर नियंत्रण लगा दिया, जिससे लगातार स्कूलों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। जिंदा रहने के लिए कई स्कूलों ने खर्चे कम किए, जिससे गुणवत्ता में कमी आई और कई स्कूल तो बंद ही हो गए। स्कूलों की स्वायत्तता पर नया हमला निजी प्रकाशकों की किताबों को प्रतिबंधित करना है। 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों को सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। इससे किताबों की कीमत में तो कमी आई है, लेकिन अभिभावक इनकी गुणवत्ता व देरी को लेकर चिंतित हैं। यद्यपि एनसीईआरटी की किताबें बेहतर हुई हैं, लेकिन पढ़ाई का पुराना तरीका कायम है। शिक्षक हैलो इंग्लिश और गूगल बोलो जैसे आश्चर्यजनक एप्स से अनजान हैं, जो भारतीय बच्चों को तेजी से अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं। शिक्षाविदों की चिंता है कि इस प्रतिबंध से भारतीय बच्चे दुनिया में हो रही क्रांतियों के बारे में जानने से वंचित हो सकते हैं, विशेषकर डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में। इससे वे ज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से भी वंचित हो सकते हैं। दुखद है कि एशिया का उच्च प्रदर्शन वाला शैक्षिक तंत्र एक उदार बहुपुस्तक नीति के विपरीत दिशा में चला गया है। इसने एक किताब और एक परीक्षा की कड़ी को तोड़कर विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाया था। चीन ने 1980 के आखिर में ही राष्ट्रीय पुस्तक नीति को छोड़ दिया था और बच्चों को कई किताबें इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे आधुनिक समाज के वास्तविक अनुभवों से जुड़ सकें। गणतंत्र बनने के 70 साल के बाद अब समय है कि निजी स्कूलों को स्वयत्तता दी जाए। 1991 के सुधारों ने उद्योगों को स्वायत्तता दी, लेकिन हमारे स्कूलों को नहीं, जो आज भी लाइसेंस राज के नीचे कराह रहे हैं। इसके बावजूद भारत के विकास में निजी स्कूलों का योगदान अमूल्य है। इनमें पढ़े लोग हमारे प्रोफेशनल, सिविल सेवा और व्यापार में उच्च पदों पर हैं। यह समय है कि भारत को अब अपना वह सामाजिक पाखंड छोड़ देना चाहिए, जो निजी स्कूलों को लाभ कमाने से रोकता है। जिंदा रहने के लिए उसे लाभ कमाना ही होगा और इससे ही गुणवत्ता बढ़ेगी व अच्छे स्कूलों की मांग पूरी हो सकेगी। इन्हें केवल नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट क्षेत्र में बदलने से क्रांति आ सकती है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में निवेश आएगा और इनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। आज भारतीय अच्छी शिक्षा के लिए खर्च करने को तैयार हैं। एक स्वतंत्र देश में किसी को एक अच्छे स्कूल या बेहतर किताब पर खर्च करने से क्यों रोका जाना चाहिए?

निजी स्कूलों पर अधिक नियंत्रण की बजाय सरकार को सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने पर फोकस करना चाहिए। इसकी शुरुआत मंत्रालय को दो कार्यों को अलग करके करनी चाहिए- 1. शिक्षा का नियमन बिना पक्षपात के करने के लिए सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों पर समान मानदंड लागू करना। 2. सरकारी स्कूलों को चलाना। आज हितों के टकराव की स्थिति है, जो प्रशासक को भ्रमित करती है और उसका परिणाम गलत नीतियां होती हैं। समय आ गया है, जब निजी स्कूलों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारी जाए और उस दिन का इंतजार किया जाए जब एडमिशन के लिए ये लाइनें छोटी होंगी और हमारी आकांक्षाएं हकीकत के निकट होंगी। हो सकता है

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य
शैक्षिक स्तंभकार मलोट

लेन-देन वाली सरकार के प्रति जागरूक हो जाइए

सामान्य जीवन स्थितियों में हम पाते हैं कि बहुत से मनुष्य अपने व्यवहार में लेन-देन वाले होते हैं। 2 मनुष्यों या 2 मानव समूहों के बीच लेन-देन वाला रिश्ता क्या होता है? यह 'तुम मुझ पर एक एहसान करो और मैं तुम पर एक एहसान करूंगा' जैसा होता है।

सामान्य जीवन स्थितियों में हम पाते हैं कि बहुत से मनुष्य अपने व्यवहार में लेन-देन वाले होते हैं। 2 मनुष्यों या 2 मानव समूहों के बीच लेन-देन वाला रिश्ता क्या होता है? यह 'तुम मुझ पर एक एहसान करो और मैं तुम पर एक एहसान करूंगा' जैसा होता है। बोलचाल की भाषा में, इसे 'क्विड प्रो क्वो' कहा जाता है। आधिकारिक निर्णयों के लिए रिश्वत लेन-देन वाली होती है। लीक हुए प्रश्नपत्रों के लिए पैसे का लेन-देन होता है। मोदी सरकार ने सरकारी एहसानों के लिए चुनावी बॉन्ड के द्वारा लेन-देन वाले व्यवहार को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। चुनावी बॉन्ड योजना का आधार सभी को समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने, सही ढंग से लेकिन देर से, पूरी योजना को रद्द कर दिया, लेकिन योजना के पीछे की मंशा पर टिप्पणी करने में संयम बनाए रखा।

कुर्सी बचाओ : 23 जुलाई, 2024 को, एन.डी.ए. सरकार ने लेन-देन वाले व्यवहार को एक नए, उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। 2024-25 के बजट के पीछे मुख्य प्रेरणा 'सरकार को कैसे बचाया जाए' थी। यह एक कुर्सी बचाओ बजट था। बजट की लेखिका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना काम बेबाकी से किया। बजट के बाद उनके और सचिवों के बजट प्रस्तावों के स्पष्टीकरण ने 2 सहयोगियों का समर्थन जीतने के लिए किए गए क्रूर प्रयास को उजागर कर दिया। 16 वोट (तेदेपा) और 12 वोट (जद-यू) के बदले में, दोनों राज्यों को बिहार में औद्योगिक नोड्स, कनैक्टिविटी परियोजनाओं और बिजली संयंत्रों के विकास के लिए और पोलावरम सिंचाई परियोजना, औद्योगिक गलियारों और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान के लिए समर्थन मिला।

सबसे अजीब आश्वासन यह था कि बाहरी सहायता को 'तेजी से' या 'व्यवस्थित' किया जाएगा, जो कि एक वादा है। तीनों (केंद्र सरकार, बिहार और आंध्र प्रदेश) के बीच हुए बड़े सौदे में, 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ मतदान करने वाले राज्य हार गए। संबंधित राज्यों के सांसदों के अनुसार जिन राज्यों के साथ धोखा हुआ वे हैं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। राज्यों के अलावा युवाओं को धोखा दिया गया। भारत के अधिकांश लोगों को कमतर आंका गया। सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ी। बेरोजगारी चरम पर है और युवा हताश हैं। सी.एम.आई.ई. के अनुसार, जून 2024 में अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत थी। स्नातकों में यह लगभग 40 प्रतिशत है। पीरियोडॉक लेबर फोर्स सर्वे से पता चला है कि केवल 20.9 प्रतिशत नियोजित लोगों को नियमित वेतन मिलता है और विडंबना यह है कि सबसे कम शिक्षित लोग सबसे कम बेरोजगार हैं।

बजट भाषण में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ई.एल.आई.) योजना का वादा किया गया था, जिसके तहत नियोक्ताओं को मौद्रिक प्रोत्साहन देकर 290 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा और केवल 500 कंपनियों में 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। विशाल संख्याएं चुनाव के बाद के एक और विशाल जुमले की ओर इशारा करती हैं। इस सौदे में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों में 30 लाख रिक्तियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। यह भी संभव है कि बहुचर्चित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) योजना, जिस पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन नौकरियों के मामले में कोई मापनीय परिणाम नहीं मिला है। बकाया शिक्षा ऋण के संबंध में ऋण माफी की सार्वभौमिक मांग का कोई संदर्भ नहीं था जिसने छात्रों और उनके परिवारों को निराशा के कगार पर पहुंचा दिया है। अग्निपथ योजना के भाग्य का भी कोई संदर्भ नहीं था, जिसने एक सैनिक और दूसरे के बीच भेदभाव किया।

गरीबों को छला गया : लोगों का दूसरा बड़ा वर्ग जो छला हुआ महसूस करता है, वह गरीब है। जाहिर है, वित्त मंत्री नीति आयोग के सी.ई.ओ. के विचार से सहमत हैं। अपनी सांस थाम लें क्योंकि भारत में गरीबों की संख्या जनसंख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। सरकार के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) ने देश में वर्तमान/नाममात्र मूल्यों पर मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (रूक्कष्टश्व) को मापा था। ग्रामीण क्षेत्रों में औसत रूक्कष्टश्व 3,094 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 4,963 रुपए था जिसका अर्थ है कि भारत के 71 करोड़ लोग प्रतिदिन 100-150 रुपए या उससे कम पर जीवन यापन करते हैं। यदि हम अंश दर अंश नीचे जाएं, तो तस्वीर और भी निराशाजनक हो जाती है। सबसे निचले 20 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 70-100 रुपए और सबसे निचले 10 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 60-90 रुपए पर जीवन-यापन करते हैं। वे गरीब हैं या नहीं इस बात को हम नहीं जानते?

वित्त मंत्री ने लोगों को 'राहत' दी

उन्होंने मौजूदा मुद्रास्फीति को 'कम, स्थिर और 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर अग्रसर' बताया;

-उन्होंने नई कर व्यवस्था में शामिल होने वाले वेतनभोगी कर्मचारी और पैंशनभोगियों को 'आयकर में 17,500 रुपए तक' की राहत दी। आबादी के निचले 50 प्रतिशत में 71 करोड़ लोग न तो वेतनभोगी कर्मचारी हैं और न ही सरकारी पैंशनभोगी, और वित्त मंत्री उनके बारे में कुछ नहीं सोच पाए। वे भी जी.एस.टी. जैसे अप्रत्यक्ष करों के रूप में कर देते हैं। लगभग 30 करोड़ दैनिक/अस्थायी मजदूर हैं और पिछले 6 वर्षों में वास्तविक रूप से उनकी मजदूरी स्थिर रही है। ऐसे तरीके हैं जिनसे गरीबों को राहत दी जा सकती है। हर तरह के रोजगार (मनरेगा के तहत काम सहित) के लिए न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन किया जा सकता है।

मनरेगा के लिए धन के आबंटन में वृद्धि के साथ, काम के औसत दिनों की संख्या वर्तमान में प्रति वर्ष लगभग 50 दिनों से बढ़कर वादा किए गए 100 दिनों के करीब हो सकती है और मुद्रास्फीति के मुद्दे से अधिक गंभीरता से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को याद रखना चाहिए कि युवाओं और गरीबों के साथ-साथ अन्य नागरिकों के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है - वोट। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने जून 2024 में 13 उप-चुनावों में करारी शिकस्त दी। महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड में चुनाव नजदीक हैं और उसके बाद 2025 में और चुनाव होंगे। युवा और गरीब यह नहीं भूलेंगे कि 23 जुलाई, 2024 को उनके साथ धोखा हुआ था।

-पी. चिदम्बरम

अप्रैल-जून तिमाही के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश पांच गुना बढ़ा

परिवहन विशेष न्यूज

एएमएफआई के अनुसार इस वर्ष जनवरी-मार्च के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 71280 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। SIP में 21262 करोड़ रुपये का निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ जून महीने में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी निवेश का आंकड़ा 21 हजार करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले महीने SIP में कुल 21262 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

नई दिल्ली। कैलेंडर वर्ष 2024 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश पांच गुना से ज्यादा बढ़ा है। एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के डाटा के अनुसार, इस दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 94,151 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। अप्रैल-जून 2023 के दौरान इनमें 18,358 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार, मजबूत आर्थिक माहौल, सरकार समर्थित वित्तीय नीतियां और शेयरों बाजारों के मजबूत रिटर्न के कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ा है।

डाटा के अनुसार, इस वर्ष जून में म्यूचुअल फंड उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) भी 59 प्रतिशत बढ़कर 27.68 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मार्च 2023 में उद्योग का एयूएम 17.43 लाख करोड़ रुपये था। एयूएम में मजबूत वृद्धि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी को भी दर्शाती है। जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फोलियो (खातों की संख्या) बढ़कर 13.3 करोड़ हो गए हैं और इसमें तीन करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफार्म ट्रेडजिनी के सीओओ त्रिवेश डी का कहना है कि इक्विटी फोलियो में यह वृद्धि विभिन्न खंडों में निवेशकों की व्यापक भागीदारी को दर्शाती है, जो बेहतर वित्तीय साक्षरता और सुलभ निवेश प्लेटफार्मों से प्रेरित है।

एएमएफआई के अनुसार, इस वर्ष जनवरी-मार्च के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 71,280 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। एसआइपी में 21,262 करोड़ रुपये का निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ जून महीने में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में भी निवेश का आंकड़ा 21 हजार करोड़ के पार पहुंच गया है। डाटा के अनुसार, पिछले महीने एसआइपी में कुल 21,262 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जो अब तक किसी माह में सबसे अधिक निवेश है। अप्रैल-जून तिमाही के दौरान एसआइपी में 62,537 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। अप्रैल-जून 2023 में एसआइपी में 43,211 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।

किस श्रेणी में कितना निवेश

श्रेणी	निवेश
थीमैटिक	46,731 करोड़
मल्टी-कैप	10,077 करोड़
फ्लैक्सीकैप	8,387 करोड़
लार्ज एंड मिडकैप	7,948 करोड़
स्मॉलकैप	7,197 करोड़
मिडकैप	6,927 करोड़
लार्ज कैप	1,991 करोड़ रुपये

33 हजार करोड़ के पार पहुंचा जुलाई में FPI निवेश

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का भारतीय बाजारों में आकर्षण बना हुआ है। यही कारण है कि घरेलू इक्विटी बाजारों में 26 जुलाई तक एफपीआइ का शुद्ध निवेश बढ़कर 33,688 करोड़ रुपये हो गया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक इक्विटी बाजारों में एफपीआई का शुद्ध निवेश 36,888 करोड़ रुपये हो गया है।

बीते सप्ताह एफपीआई ने कुल पांच में से दो सत्रों में खरीदारी और तीन में बिक्री की। सप्ताह के दौरान एफपीआई ने शुद्ध रूप से 2,918.16 करोड़ रुपये का निवेश किया। डेट या बॉन्ड बाजारों की बात करें तो 26 जुलाई तक एफपीआई 19,223 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं।

कन्फर्म टिकट के लिए मास्टर लिस्ट के साथ कई टिप्स आएंगे काम, चुटकी में बुक हो जाएगी तत्काल टिकट

रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। कई लोग त्योहार के मौके पर अपने घर जाना चाहते हैं पर ट्रेन की कन्फर्म टिकट न मिलने की वजह से वह प्लान कैंसिल कर देते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में आसानी से तत्काल कंफर्म टिकट बुक करने के लिए कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे।

नई दिल्ली। 19 अगस्त 2024 (सोमवार) को रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2024) का त्योहार है। त्योहार के मौके पर कई लोग अपने परिवार से मिलने जाते हैं। इसके लिए वह पहले ही ट्रेन की टिकट बुक (Train Ticket Book) कर लेते हैं। लेकिन, कई लोग ऑफिस की छुट्टी कंफर्म होने के बाद टिकट बुक करते हैं और तब तक कंफर्म सीट खत्म हो जाती है।

ऐसी स्थिति में कंफर्म सीट के लिए तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) काफी अच्छा ऑप्शन रहता है, लेकिन इसके लिए भी कम समय रहता है। तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग के लिए आप कुछ टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टिप्स के बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं।

IRCTC ऐप से टिकट बुकिंग

आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। इस ऐप में आप पहले ही सभी जानकारी को सेव कर लें ताकि कम समय में टिकट बुकिंग हो जाएं। आपको पहले से ही ट्रेन का नाम और नंबर आदि डिटेल्स को भी निकाल लेना चाहिए।

मास्टर लिस्ट तैयार करें

आपको मास्टर लिस्ट पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। मास्टर लिस्ट में आपको यात्रियों के नाम, बर्थ प्रेफरेंस और फूड प्रेफरेंस आदि डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। अगर यह सभी डिटेल्स पहले से सेव रहती है तो टिकट बुकिंग करते समय आपका समय काफी बच जाएगा। मास्टर लिस्ट बनाने के लिए आपको IRCTC अकाउंट के My Profile सेक्शन जाना होगा।

e-Wallet का इस्तेमाल करें

तत्काल टिकट बुकिंग का समय काफी कम होता है। ऐसे में कई बार पेमेंट न होने की वजह से भी मौका हाथ से छूट जाता है। इस स्थिति में आपको इंटरनेट बैंकिंग की जगह UPI वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल, इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन, पासवर्ड और ओटीपी आदि भरने में काफी समय लग जाता है।

कम समय में पेमेंट करने के लिए आप IRCTC के e-Wallet का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। e-Wallet के जरिये चुटकी में पेमेंट हो जाती है और यह काफी समय भी बचाता है।

आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, वीजा वर्ल्डवाइड और मणप्पुरम फाइनेंस पर लगाया जुर्माना, नियमों का नहीं कर रहे थे पालन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने तीन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने मणप्पुरम फाइनेंस और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ ही वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड पर 2.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 41.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वीजा वर्ल्डवाइड, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज और मणप्पुरम फाइनेंस पर रेगुलेटरी अनुपालन न करने के कारण जुर्माना लगाया है। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड पर 2.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 41.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर दो अलग-अलग मामलों में 87.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

RBI के अनुसार, मणप्पुरम फाइनेंस और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर ये जुर्माना नो योर कस्टमर (Kyc) निर्देशों के कुछ नियमों का पालन न करने के कारण जुर्माना लगा है। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज और वीजा वर्ल्डवाइड को विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कंपाउंडिंग ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। आरबीआई ने पाया कि वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड ने केंद्रीय बैंक से आवश्यक विनियामक मंजूरी प्राप्त किए बिना भुगतान प्रमाणीकरण समाधान लागू कर दिया था। नतीजतन, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें उससे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया।

मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज को KYC जरूरतों पर RBI के निर्देशों का पालन न करने वाला पाया गया। इन संस्थाओं को भी नोटिस जारी किए गए और उनके लिखित जवाबों पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा, RBI ने कहा कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने एस्क्रो अकाउंट बैलेंस में कमी के मामलों की सूचना दी और उल्लंघन को कम करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

सुनवाई के दौरान किए गए समझौता आवेदन का विश्लेषण करने के बाद RBI ने निर्धारित किया कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के उल्लंघन को कम किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं।

रिफंड पाने के लिए रिटर्न में बढ़ा-चढ़ाकर फर्जी दावे करने से बचें करदाता, ऐसा करना दंडनीय अपराध

आयकर विभाग ने बताया था कि करदाताओं को समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही तरीके से दाखिल करने चाहिए। विभाग ने कहा रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है जिससे देरी हो सकती है। आईटीआर सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है। किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा।

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्च संबंधी फर्जी दावे नहीं करें और अपनी कमाई को कम करके नहीं दिखाएं। विभाग ने कहा कि बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है। सभी करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जिसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, 26 जुलाई तक पांच करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।

हाल ही में आयकर विभाग ने बताया था कि करदाताओं को समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही तरीके से दाखिल करने चाहिए। विभाग ने कहा 'रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है। आईटीआर सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है। किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा। आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने वाले करदाताओं से गलत स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) राशि का दावा नहीं करने, अपनी आय को कम नहीं बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताने का आग्रह किया है।

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें, अपनी आय को कम न बताएं या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं क्योंकि यह दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने का सत्र उन सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगा जिनके खातों का ऑडिट नहीं किया जाना है।

आयकर विभाग और उसके प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, 26 जुलाई तक पांच करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक संचार में, आयकर विभाग ने करदाताओं से समय पर रिफंड प्राप्त करने के लिए अपने रिटर्न को सही तरीके से दाखिल करने को कहा। रिफंड के दावे सत्यापन जांच के अधीन हैं, जिससे देरी हो सकती है। आईटीआर को सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया तेज होती है। किए गए दावों में कोई भी विसंगति संशोधित रिटर्न (करदाता द्वारा दाखिल की जाने वाली) के लिए अनुरोध को प्रेरित करेगी।

1 अगस्त से फिसलन और क्रैक वाले फुटवियर से मिलेगा छुटकारा, BIS सर्टिफाइड जूते-चप्पल की ही होगी बिक्री

इसके बदले ग्राहक को पहले की तुलना में पांच प्रतिशत तक अधिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है क्योंकि बीआईएस सर्टिफिकेट लेने के लिए निर्माताओं को कई गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा और इससे उनकी लागत बढ़ेगी। भारत में घरेलू स्तर पर सालाना 1.25-1.5 लाख करोड़ रुपये का फुटवियर का कारोबार होता है। पिछले साल ही फुटवियर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

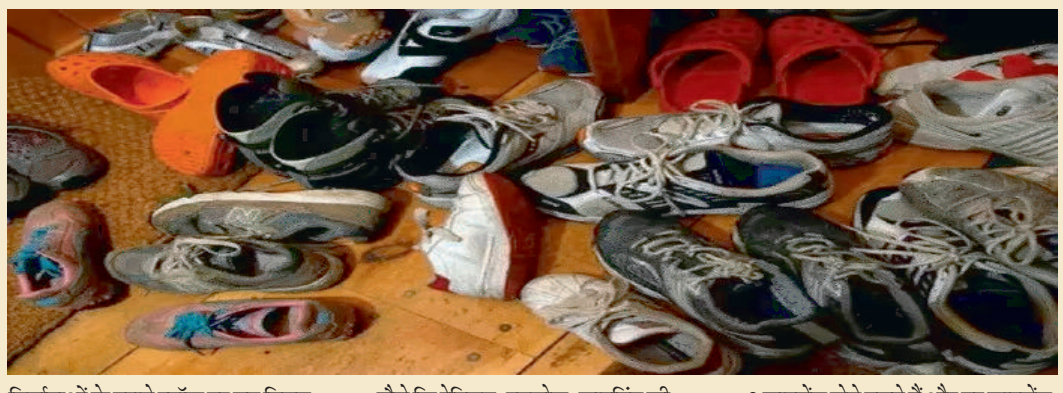

नई दिल्ली। अब आपके फुटवियर (जूते-चप्पल) पहले की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे। उनमें फिसलन नहीं होगी, क्रैक भी नहीं आएगा और फुटवियर के ऊपर का सोल भी अधिक लचीला होगा। दो माह चलने वाला फुटवियर अब सात-आठ माह चलेगा। खराब फुटवियर की वजह से होने वाले घुटने दर्द की शिकायत भी कम हो जाएगी। यह सुविधा इसलिए मिलने जा रही है क्योंकि 1 अगस्त से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से सर्टिफायड फुटवियर की ही बिक्री बाजार में हो पाएगी।

कीमतों में होगा इजाफा

इन सुविधाओं के बदले ग्राहक को पहले की तुलना में पांच प्रतिशत तक अधिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है क्योंकि बीआईएस सर्टिफिकेट लेने के लिए निर्माताओं को कई गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा और इससे उनकी लागत बढ़ेगी। हालांकि अभी सालाना 50 करोड़ से कम का कारोबार करने वाले फुटवियर निर्माता को बीआईएस के इस नियम से मुक्त रखा गया है। 50 करोड़ सालाना से अधिक के टर्नओवर वाले फुटवियर निर्माताओं के पुराने स्टॉक पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे अपने पुराने स्टॉक की जानकारी बीआईएस की साइट पर अपलोड करेंगे।

सालाना 1.25-1.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार

भारत में घरेलू स्तर पर सालाना 1.25-1.5 लाख करोड़ रुपये का फुटवियर का कारोबार होता है। पिछले साल ही फुटवियर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। गुणवत्ता नियम पर अमल के लिए फुटवियर निर्माताओं को कई माह का समय दिया गया था। रोजाना चार लाख जोड़ी फुटवियर बनाने की क्षमता रखने वाली कंपनी वीकेसी के चेयरमैन और कनफेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष वी. नौशाद ने बताया कि अब तक फुटवियर बीआईएस के 1400 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और निर्माता इस नियम के मुताबिक अपना उत्पादन शुरू कर चुके हैं।

क्वालिटी होगी पहले से बेहतर

गुणवत्ता नियम के तहत मुख्य रूप से फुटवियर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे कि रेक्सिन, इनसोल, लाइनिंग की कमेकिल जांच करनी होगी। ऊपरी भाग के मेटेरियल को टीयर स्ट्रेंथ और बेहतर लचीलापन की जांच में पास होना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को एक निश्चित परिभाषा वाली गुणवत्ता का माल मिले और भारतीय फुटवियर उत्पाद की वैश्विक बाजार में भी ब्रांडिंग हो सके। इससे निर्यात को लाभ मिलेगा। साथ ही जूते-चप्पलों की क्वालिटी पहले से काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। सिफी के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि सरकार ने जून, 2025 तक पुराने माल को बेचने की अनुमति दी है। इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि लगभग एक तिहाई स्टॉक पाइपलाइन में रहता है। वहीं बड़े निर्माताओं के लाखों रिटेलर्स होते हैं और उन रिटेलर्स के स्टॉक का हिसाब रखना आसान नहीं होता है। इसलिए रिटेलर्स को भी अपने स्टाक अपलोड की अनुमति मिलनी चाहिए।

लाइसेंस लेने में कितना खर्चा

फुटवियर निर्माताओं के मुताबिक बीआईएस नियम के पालन के लिए उन्हें 6-8 लाइसेंस लेने पड़ते हैं और हर लाइसेंस पर 2-3 लाख रुपए खर्च होते हैं। यह लागत कम होनी चाहिए। फुटवियर सेक्टर में 70 प्रतिशत से अधिक निर्माता 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं और उनपर यह नियम लागू होने के बाद ही पूर्ण रूप से गुणवत्ता वाले फुटवियर बाजार में बिकेंगे। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कुछ समय के बाद छोटे निर्माताओं को भी बीआइएस नियम के दायरे में लाया जाएगा।मंत्रालय फुटवियर निर्माताओं की मांग पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) भी लगाने के पक्ष में है।

अभी चीन से बड़ी संख्या में सस्ते फुटवियर का आयात होता है और अब गुणवत्ता नियम लागू होने से घरेलू उत्पादकों की लागत बढ़ेगी जिससे उनका माल अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाएगा। अगर चीन से सस्ते में माल आता रहा तो उनके फुटवियर की बिक्री घरेलू स्तर पर प्रभावित होगी। इसलिए मंत्रालय ने उन्हें अपनी वास्तविक लागत का पूरा ब्योरा देने के लिए कहा है ताकि उसके मुताबिक एमआईपी की घोषणा की जा सके।

तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई नियम होंगे और सख्त DPIIT ने मंत्रालयों के विचार जानने के लिए तैयार किया मसौदा

DPIIT ने इस मुद्दे पर विभिन्न मंत्रालयों के विचार जानने के लिए एक मसौदा नोट जारी किया है। अधिकारी ने कहा कि प्रचार गतिविधियों में प्रॉक्सी विज्ञापन विभिन्न तरीकों से ब्रांड प्रचार और ब्रांड के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। अधिकारी ने कहा तंबाकू में एफडीआई प्रतिबंधित है और क्षेत्र की प्रचार-प्रसार गतिविधियों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तंबाकू क्षेत्र में प्रचार-प्रसार की गतिविधियों पर रोक और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को और सख्त करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनियां इस बारे में नियमों को 'दरकिनार' करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके मद्देनजर सरकार एफडीआई नियमों को सख्त करना चाहती है। फिलहाल तंबाकू के सिगार, चुरट, सिगारिलो और सिगरेट की मैन्यूफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर रोक है। हालांकि, तंबाकू क्षेत्र में किसी तरह के प्रौद्योगिकी सहयोग में एफडीआई की अनुमति है।

इसमें फ्रेंचाइजी के लिए लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम और प्रबंधन अनुबंध शामिल हैं। अधिकारी ने कहा, तंबाकू में एफडीआई प्रतिबंधित है, और क्षेत्र की प्रचार-प्रसार गतिविधियों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे उत्पादों का प्रचार करके कुछ कंपनियां एक ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश करती हैं जहां तस्करी बढ़ती है। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस मुद्दे पर विभिन्न मंत्रालयों के विचार जानने के लिए एक मसौदा नोट जारी किया है। अधिकारी ने कहा कि प्रचार गतिविधियों में प्रॉक्सी विज्ञापन, विभिन्न तरीकों से ब्रांड प्रचार और ब्रांड के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

मंत्रालय ने 2016 में तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी पेश किया था। प्रस्ताव के तहत मंत्रालय ने क्षेत्र में फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम और प्रबंधन अनुबंधों के लाइसेंस में एफडीआई पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, तंबाकू किसान संघों और कंपनियों सहित कुछ हलकों की चिंताओं के कारण सरकार इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकी थी। घरेलू तंबाकू उद्योग पर मुख्य रूप से आईटीसी लिमिटेड का प्रभुत्व है।

ओलंपिक में खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका मिला -नरेंद्र मोदी

दुनिया के 70% बाघ हमारे देश में है मन की बात सुनकर एक पौधा मां के नाम लगाया

परिवहन विशेष न्यूज

भीलवाड़ा। भाजपा प्रदेश नेतृत्व एवं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के निर्देशानुसार भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में मन की बात सुनकर एक पौधा मां के नाम लगाया, भीलवाड़ा शहर का मुख्य आयोजन गणेश मंडल के वार्ड नंबर 17 स्थित ऋषि वाटिका के पास शाइनिंग स्टार स्कूल ,पुलिस लाइन साथ ही जिला कार्यालय भीलवाड़ा पर रखा गया

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाये. भारत की दुनिया के इस ओलंपिक से अलग , कुछ दिन पहले दिल्ली में भी एक ओलंपिक हुआ है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड , इस ओलंपियाड में भारत के छात्रों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता है . इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पियाड में 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और दिल्ली में हुए ओलंपियाड में ओवरऑल हमारी टीम टॉप फाइव में आने में सफल रही है . इन सभी छात्रों ने देश का नाम रोशन किया है.

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मन की बात एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं ऐसा ही एक प्रयास है 'प्रोजेक्ट परी' अब आप 'परी' सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा यह परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है

'परी' यानी 'पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया' प्रोजेक्ट , 'परी' पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है . आप देखते होंगे सड़कों के किनारे दीवारों पर अंडरपास में इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है वही हमारे कलर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है.,उदाहरण के लिए 'दिल्ली के भारत मंडपम' को ही ले लीजिए,नरेन्द्र मोदी ने देश वासियों को संबोधित करते हुए कहा प्यारे देशवासियों 'मन की बात' में अब बात रंगों की , ऐसे रंगो की जिन्होंने

हरियाणा के रोहतक जिले की ढाई सौ से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए , महिलाएं छोटी-छोटी दुकानें और छोटे-मोटे काम कर गुजारा करती थी लेकिन हर किसी में आगे बढ़ाने की इच्छा होती है , इसलिए इन्होंने 'उन्नति' सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगो में ट्रेनिंग हासिल की , कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली यह महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही है इनके बनाए बेड कवर , साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है ,देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है , 7 अगस्त को हम 'नेशनल हैंडलूम डे' मनाएंगे

आजकल जिस तरह हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है वह वाकई बहुत सफल है जबर्दस्त है. मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा की बहुत से लोग अपने यहां के ऐसे लोकल प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #माय प्रोडक्ट मी प्राइस के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें आपका एक छोटा सा प्रयास अनेक आम लोगों की जिंदगी बदल देगा,साथियों हैंडलूम के साथ-साथ मैं खादी की बात भी करना चाहूंगा. आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं मुझे यह बताते हुए भी आनंद आ रहा है खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार डेढ़ लाख करोड रुपए के पार पहुंच गया है. खादी की बिक्री कितनी बड़ी है 400 परसेंट. खड़ी की हैंडलूम की यह बढ़ती हुई बिक्री रोजगार के नए अवसर बना रही है और आपने यदि अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे इस साल से शुरू कर ले , अगस्त का महीना आ ही गया है यह आजादी मिलने का महीना है क्रांति का महीना है . इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'मन की बात' में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है . हर परिवार को चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है 'मानस'. ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में यह बहुत बड़ा कदम है कुछ दिन पहले ही 'मानस' की हेल्पलाइन और पोर्टल को लांच किया गया है , सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है अगर किसी के पास इससे जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो वह इसी नंबर पर कॉल करके कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा भी कर सकते हैं 'मानस' के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है . भारत को ड्रग्स मुक्त बनाने में जुटे सभी लोगों से सभी परिवारों से सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि 'मानस हेल्पलाइन' का भरपूर उपयोग करें

मेरे प्यारे देशवासियों कल दुनिया भर में 'टाइगर डे' मनाया जाएगा , भारत में तो टाइगर , बाघ , हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है हम सब बाघ से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए , जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है. हमारे देश में ऐसे कई गांव है जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है 'कुल्हाड़ी बंद पंचायत' राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ 'कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान' बहुत दिलचस्प है , स्थानीय समुदाय ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे . एक बार जंगल फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है.

मुझे खुशी है कि जन भागीदारी , बाघो के संरक्षण में बहुत काम आ रही है ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है आपको यह जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ है उनमें से 70% बाघ हमारे देश में है , तभी तो हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी है. साथियों बाघ बढ़ने के साथ-साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है,पिछले 'मन की बात' कार्यक्रम में आपसे 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम की चर्चा की, मुझे खुशी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर शहर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ यहां 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए. अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी मां और धरती मां दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का अहसास होगा

कार्यक्रम में कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाडा नगर परिषद सभापति राकेश पाठक पूर्व जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली, पूर्व जिला महामंत्री कल्पेश चौधरी,बाबूलाल टाक, ज्योति आशीर्वाद जिला संयोजक विजय हिंगोरानी, मंडल अध्यक्ष घनश्याम घनश्याम सिगीवाल, राधेश्याम सोमानी, , भेरु मेघवंशी, नरपत सिंह, गोपाल पारीक, लाभ शंकर चौबे ,प्रकाश भील ,अशोक खंडेलवाल, धर्मेश ,हेमंत, पायक गिरिराज मेघवाल ,पवन राठी, राकेश गुर्जर आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

तिलक / टीका

सनातन परंपरा में माथे पर तिलक लगाने का काफी महत्व माना गया है। विवाहित स्त्रियां माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती हैं. पूजा के समय या किसी भी शुभ कार्य के मौके पर भी मस्तक पर तिलक जरूर लगाया जाता है। अलग अलग मौकों पर अलग चीजों से तिलक लगाने का चलन है। ये संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है-:

धार्मिक मान्यता-:

धार्मिक मान्यता के अनुसार मस्तक के बीचोंबीच भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा (त्रिदेव) का निवास होता है. उस स्थान पर ही तिलक भी लगाया जाता है।मान्यता है कि इससे ₹भगवान त्रिदेव₹ प्रसन्न होते हैं। महिलाएं इसे मातारानी का आशीर्वाद मानकर मस्तक पर लगाती हैं। इसके अलावा इस स्थान को ₹त्रिवेणी या संगम₹ भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर शरीर की तीन नाड़ियां एक साथ मिलती हैं।यही स्थान मन व गुरु का भी होता है, इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस स्थान पर तिलक लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का तेज बढ़ता है। हमारी संस्कृति में प्रातः काल स्नान के बाद तिलक लगाने की परंपरा वैदिक काल से है। और तिलक लगाने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है।

वैज्ञानिक वजह-:

हमारे शरीर में सात चक्र होते हैं, इन्हें ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. मस्तक के बीचोंबीच आज्ञाचक्र होता है. यही स्थान ₹पीनियल ग्रन्थि₹का होता है. जब उस स्थान पर तिलक लगाया जाता है तो पीनियल ग्रन्थि का उद्दीपन होता है. इससे शरीर के सूक्ष्म और स्थूल अवयन जागृत होते हैं।मस्तक पर तिलक लगाने से बीटाएंडोरफिन और सेराटोनिन नामक रसायनों का स्राव भी संतुलित होता है। इससे मस्तिष्क शांत होता है। एकाग्रता बढ़ती है, गुस्सा और तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। कुछ वर्षों तक लगातार तिलक लगाने से आपकी मूल्यांकन क्षमता और दूरदर्शिता में अद्भुत विकास होता है।

प्रतिदिन तिलक लगाने से धीरे-धीरे आपके अंदर "सिक्स्थ सेंस" का जागरण होता है., जिसकी वजह से आप भविष्य में आने वाली आपात घटनाओं व समस्याओं का आभास आपको होने लगता है, और आप कॉफी समस्याओं व दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।

सबसे उत्तम तिलक-:

सबसे उत्तम तिलक केसर, हल्दी, कुमकुम, रोली, सिन्दूर और चंदन के होते हैं, इनमें से कोई भी तिलक लगाएंगे वो आपको निश्चित लाभ देगा।

ध्यान रहे कृत्रिम वस्तुओं का तिलक कोई लाभ नहीं देता। अतःतिलक हमेशा शुद्ध व प्राकृतिक वस्तुओं का ही लगायें जैसे-: चंदन, हल्दी, केसर इत्यादि। तिलक को आप गंगाजल से या गुलाब जल से गिला कर सकते हैं।तिलक लगाने का लाभ तभी मिलेगा जब नियमित रूप से तिलक लगाया जाए और कम से कम दो- पहर तक तिलक माथे पर रहना आवश्यक है।

निश्चित मानिए जब आप अपने इष्ट प्रभु के नाम का प्रतिदिन प्राकृतिक वस्तुओं का तिलक लगाना शुरू करेंगे तो आपके विचार भी सुंदर होंगे और आपका चेहरा भी आकर्षक लगेगा।।

हिमाचल के दो जिलों में बाढ़ तो उत्तराखंड में फटा बादल, शिमला में भूस्खलन से गाड़ियां दबीं

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम की मार जारी है। कई जिलों में बारिश का यलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भूस्खलन में कई गाड़ियां दब गईं। कुल्लू जिले के पलचान गांव तक ब्यास नदी का पानी पहुंच गया। गांव के स्कूल भवन को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में आदि कैलास मार्ग पर नाहल में बादल फटा है।

नईदिल्ली। हिमाचल और उत्तराखंड में वर्षा का दौर जारी है। लाहुल स्पीति व कुल्लू जिला में बाढ़ आने से नुकसान हुआ है। दोनों स्थानों पर 34 घर खाली करवाने पड़े हैं। वहीं, शिमला के पंथाघाटी में भूस्खलन के कारण गाड़ियां मलबे में दब गईं। शनिवार रात लाहुल स्पीति जिला में मयाड़ नाले में बाढ़ आने से पानी और मलबा करपट गांव में घरों तक पहुंच गया।

कूल्लू में बढ़ा ब्यास का जलस्तर

दूसरी घटना कुल्लू जिले पलचान गांव की है। रविवार सुबह भारी वर्षा के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी ने पलचान गांव का रुख कर लिया, जिससे भारी भूस्खलन होने लगा। देखते ही देखते पानी घरों तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए टीम खाद्य सामग्री व जरूरी सामान लाई थी। अधिकतर लोगों ने टेंट में तो कुछ ने दूसरे गांव में शरण ली है।

हिमाचल के इन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

10 बीघा भूमि पर सब्जियों की फसल तबाह हो गई है। गांव के स्कूल भवन को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कई स्थानों में भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 29 से 31 जुलाई तक अधिकतर स्थानों पर भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है। 29 जुलाई को ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर जिलों में आंधी चलने के साथ भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है।

आदि कैलास मार्ग पर नाहल में बादल फटा

उत्तराखंड मे उच्च हिमालयी व्यास घाटी में आदि कैलास मार्ग पर नाहल में बादल फटा है। इससे नाहल नाला ऊफान पर आ गया और कुछ मीटर सड़क बह गई। यहां पर निर्माणाधीन पुल सुरक्षित है। बीआरओ क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का काम कर रहा है। मार्ग बंद होने से कुटी, ज्योलिंगकोंग का सड़क संपर्क भंग है।

उत्तराखंड के पांच जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट

उत्तराखंड में मानसून की वर्षा का दौर कुछ धीमा पड़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि अगले 12 घंटे में देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर में भी कहीं-कहीं एक से दो दौर तेज वर्षा हो सकती है। इन जनपदों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बादल छाये रहने और कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है।

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बाद अब यूजर्स के सामने नई मुसीबत! सरकारी एजेंसी ने किया आगाह

दुनियाभर के कंप्यूटर ऑपरेशन को प्रभावित करने वाली माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की घटना से उबरने के बाद अब क्राउडस्ट्राइक यूजर्स नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। इस बार खतरा उनके पूरे डाटा को लेकर है जिसे लेकर केंद्रीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सीईआरटी-इन ने आगाह किया है। एजेंसी ने यूजर्स को एक फिशिंग स्कैम से बचने की सलाह दी है जो तेजी से बढ़ रहा है।

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज (गड़बड़ी) का लाभ उठाकर क्राउडस्ट्राइक यूजर्स को 'फिशिंग' हमले के जरिये निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि हमलावर चकमा देने के लिए खुद को 'क्राउडस्ट्राइक सपोर्ट स्टाफ' बता रहे हैं। गौरतलब है कि क्राउडस्ट्राइक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो साइबर सुरक्षा मुहैया कराती है। 'क्राउडस्ट्राइक फॉल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर' के अपडेट के दौरान एरर आ जाने के कारण 19 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली ध्वस्त हो गई थी।

डाटा लीक होने का खतरा

भारतीय कंप्यूटर अपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी इन) द्वारा शनिवार को जारी किए गए परामर्श में कहा गया, 'ये हमले यूजर्स को कंप्यूटर में अज्ञात मैलवेयर इंस्टाल करने के लिए लुभा सकते हैं, जिससे संवेदनशील डाटा लीक होने, कंप्यूटर प्रणाली के ठप पड़ने और डेटा लीक होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। सिस्टम क्रैश भी हो सकता है।'

वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार पांच दिवसीय लोक अदालत आज से, घटेगा मुकदमों का बोझ

परिवहन विशेष न्यूज

सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ घटेगा। लोक अदालत का आयोजन पांच दिनों तक होगा। लोक अदालत में वैवाहिक विवाद संपत्ति विवाद मोटर दुर्घटना दावा जमीन अधिग्रहण मुआवजा सर्विस और लेबर आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। आपसी सहमति के आधार पर अदालत मामलों का निपटारा करेंगी।

नई दिल्ली। वैसे तो आपसी समझौते से साहार्दपूर्ण माहौल में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक लोक अदालतों का आयोजन होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से शुरू हो रही पांच दिवसीय विशेष लोक अदालत कुछ खास है। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर पहली बार पांच दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है।

रजामंदी से विवादों को निपटाया जाएगा

सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अदालत सहित सुप्रीम कोर्ट की सात अदालतों में विशेष लोक अदालतें लगेंगी जो मध्यस्थता करते हुए पक्षकारों की रजामंदी से विवादों को निपटाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष अदालत 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलेगी और इसमें पक्षकारों की सहमति से सौहार्दपूर्ण तरीके से हजारों मामले निपटने की उम्मीद है। इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों में भी कुछ कमी आएगी।

मुख्य न्यायाधीश ने की थी ये अपील

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गत 18 जून को ही सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर एक वीडियो संदेश जारी कर वकीलों और पक्षकारों से अपने विवादों को हल कराने के लिए विशेष लोक अदालत में मामले पंजीकृत कराने की अपील की थी। तभी से विशेष लोक अदालत में निपटारे के लिए केस पंजीकृत होने शुरू हो गए थे।

14 हजार केस सुनवाई के लिए पंजीकृत

उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि इस क्रम में विभिन्न श्रेणियों के 14 हजार से ज्यादा केस विशेष लोक अदालत में सुनवाई के लिए पंजीकृत हुए उस लिस्ट से सुनवाई के लिए केसों को छांटा गया है। सोमवार को सात अदालतों में विशेष लोक अदालत के कुल 300 से ज्यादा केस निपटारे के लिए लगे हैं। जिसमें से चीफ जस्टिस कोर्ट में 68 ऐसे केस लगे हैं बाकी अदालतों में औसतन 45 से 50 केस लगे हैं।

सुबह रुटीन के मुकदमों की होगी सुनवाई

यह केस सुप्रीम कोर्ट की रोजाना सुनवाई की सूची में लगे केसों से अलग है। तय व्यवस्था के मुताबिक सोमवार से शुरू होने वाली विशेष लोक अदालत में चीफ जस्टिस की अदालत से लेकर सात अदालतें पहले सुबह रुटीन के मुकदमों की सुनवाई करेंगी। भोजनावकाश के बाद दो बजे से विशेष लोक अदालत के मामलों का निपटारा किया जाएगा। पांच दिन चलने वाली विशेष लोक अदालत में यही व्यवस्था रहेगी।

विशेष लोक अदालत के लिंक जारी

विशेष लोक अदालत में पक्षकारों और वकीलों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है और इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सातों अदालतों में लगने वाली विशेष लोक अदालत के लिंक जारी हो चुके हैं।

इन विवादों का होगा निपटारा

पक्षकार देश के किसी भी हिस्से से सुनवाई में जुड़ सकते हैं। विशेष लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, सर्विस और लेबर आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालतें मध्यस्थता के जरिए विवाद के हल का मंच उपलब्ध करा लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान की राह बनाती हैं।

आलू संकट के बीच सब्जी कीमतें भी बढ़ गई , ओड़शिा में आम लोगों परिशान

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेस्वर। आलू संकट के बीच सब्जी कीमतें भी बढ़ गई हैं । राजधानी सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में, अधिकांश घरेलू कीमतें 50 रुपये से ऊपर हैं। जबकि राजधानी में आलू की कीमत अब 45 रुपये प्रति किलो है, आलू 45 रुपये, वेंडी 50 रुपये, टमाटर 50 रुपये, प्याज 40 रुपये, केकड़ा 50 रुपये, झोड़ंग 80 रुपये, बीन्स 100 रुपये। कटक में आलू की कीमत 45 रुपये, टमाटर 60 रुपये, सेम 30 रुपये, प्याज 35 रुपये, जूडांग 30 रुपये बिक रहा है । बरसात के मौसम में सब्जी की कीमतें आम तौर पर कम होती हैं। लेकिन चूंकि अधिकांश सब्जी दूसरे राज्य से आते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जीवन यापन की लागत अधिक है।

'मौत नहीं आपराधिक लापरवाही', कांग्रेस ने दिल्ली कोचिंग हादसे को बताया सिस्टम की नाकामी

कांग्रेस ने दिल्ली के राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुई तीन छात्रों की हत्या पर सवाल उठाते हुए इसे आपराधिक लापरवाही बताया है। पार्टी ने इसे सिस्टम की नाकामी बताते हुए जिम्मेदार अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। राहुल खरगे और प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से घटना पर रोष जाहिर किया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक प्रमुख कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की डूब कर हुई मौत को कांग्रेस ने आपराधिक लापरवाही बताते हुए तमाम सरकारी संस्थाओं की भयंकर नाकामी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही पार्टी ने इसके लिए जिम्मेदार संस्थाओं की तत्काल जवाबदेही तय करने की मांग की है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023